Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

SHRI VED PRAKASH GOYAL: Sir, I move :

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: So, your reply on this Bill in the House was your maiden speech.

SHRI VED PRAKASH GOYAL: I had my maiden speech yesterday itself on another legislation.

THE DEPUTY CHAIRMAN: But today, you have confirmed it. Now, we adjourn for lunch till 2 p.m. When we re-assemble, we will take up the Short Duration Discussion on the drought situation in various parts of the country.

The House then adjourned for lunch, at fifty-six minutes past twelve of the clock.

The House re-assembled after lunch at five minutes past two of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

SHORT DURATION DISCUSSION

Drought situation in various parts of the country

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान): सभापति महोदय, यह अल्पकालिक चर्चा देश के अंदर व्यापक सूखे की मार के संबंध में लायी गयी है । महोदय, भारत व्यापक सूखे की चपेट में है और ऐसी स्थिति में जनता की आवश्यकताओं को समझने वाले एक राजनीतिक नेतृत्व, सतर्क और निपुण प्रशासन की जरूरत है । यह करोड़ों किसानों, खेत मजदूरों के लिए विकट संकट की घड़ी है । लोकतंत्र में शासन का मुख्य कार्य सूखा प्रभावित को तुरंत राहत पहुंचाना होना चाहिए, लेकिन वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक मशीनरी इस राष्ट्रीय विपदा की तरफ आवश्यक ध्यान नहीं दे रहा है । वह इस समस्या के प्रति लापरवाह है । सत्तारूढ़ तबका राहत कार्यों के संबंध में, खासकर केन्द्र और राज्य, विफल साबित हो रहे हैं । आज देश के कई राज्यों में वर्षा कम होने के कारण सूखे की स्थिति बनी हुई है । विशेषकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे राज्यों के अंदर तो लोगों के सामने अकाल की भयंकर समस्या पैदा हो गई है । महोदय, राजस्थान के अंदर तो लगातार चौथी बार अकाल की भीषण स्थिति बनी है । राजस्थान के करीब 41 हजार गांवों में से 40 हजार से अधिक गांवों में अब की बार अकाल की भयंकर स्थिति है, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था और अनुमान लगाकर संकट के निवारण के लिए योजनाएं बना ली थीं व केन्द्र सरकार से सहायता के लिए आग्रह हेतु अपना प्लान पहले से ही भेज दिया था ।

महोदय, इस वर्ष राज्य के 32 जिलों के 40,689 गांव सूखे की चपेट में हैं । प्रदेश की 4.47 करोड़ जनसंख्या व 4.51 करोड़ पशु-धन सूखे से प्रभावित है । प्रदेश में खरीफ की बुवाई के सामान्य लक्ष्य 129 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के विरुद्ध 60.89 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हुई जिस में जुलाई माह में वर्षा कम होने के कारण 50 परसेंट बुवाई नष्ट हो गयी । उसके बाद वर्षा न होने के कारण जो बुवाई की गई थी वह लगभग सारी नष्ट हो गई है । आज राजस्थान की जनता इस अकाल की मार से भयंकर दुखी है ।

महोदय, राजस्थान की सरकार ने इस अकाल से क्षति का अनुमान 60,519.76 करोड़ रुपए लगाया था, जो केन्द्र सरकार से सहायता के रूप में मांगा था और काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं मांगा था । केन्द्र सरकार ने राजस्थान सरकार को उसकी जो 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की मांग थी, उसके स्थान पर 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं ही उपलब्ध कराया, जो राजस्थान सरकार ने उठा भी लिया है । राजस्थान का एक दुर्भाग्य यह भी है कि राजस्थान के बारे में केन्द्रीय मंत्री और कई केन्द्रीय नेता यह कहते हैं कि राजस्थान सरकार को जो सहायता दी जा रही है वह राजस्थान सरकार नहीं उठा रही है । इस तरह के शब्दों के भ्रमजाल में फंसाया जाता है । मैं जानना चाहता हूँ कि कौनसा ऐसा गेहूं है, जो राजस्थान सरकार नहीं उठा रही ? अगर हम इस मामले में दूसरे राज्यों से तुलना करते हैं तो राजस्थान सरकार बेहतर काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है । जो भी उसे मिलता है, उसका ज्यादा परसेंटेज वह अन्य राज्यों की तुलना में उठा रही है । जहां तक एपीएल गेहूं की बात है, राजस्थान सरकार ने 4.9 परसेंट उठाया है, जबकि गुजरात ने 0.4 परसेंट उठाया है, उत्तर प्रदेश ने 0.1 परसेंट उठाया है । यह एपीएल गेहूं कैसा है ? यह खराब गेहूं है, जो भीग गया है, गीला हो गया है । बाजार में जब इससे अच्छा और सस्ता गेहूं मिल जाता है तो फिर इस गेहूं को कोई क्यों लेगा, गरीब आदमी इसे क्यों लेगा ? इस गेहूं को न उठाने का कारण यही है कि जब कोई दूसरा इसे लेगा ही नहीं तो राज्य सरकार इसको उठाकर कहां ले जाएगी? जब इसे खरीदने वाला कोई नहीं होता तो राज्य सरकार के ऊपर यह दोष क्यों मढ़ दिया जाता है कि राज्य सरकार यह गेहूं नहीं उठा रही ?

महोदय, इसी के साथ ही अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो गेहूं दिया जाता है, उसकी स्थिति भी मैं आपको बताना चाहता हूँ । राजस्थान सरकार ने अंत्योदय योजना में 94.5 परसेंट अपना कोटा उठाया है, गुजरात सरकार ने 76.9 परसेंट अपना कोटा उठाया है, झारखंड सरकार ने 74 परसेंट अपना कोटा उठाया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 49.2 परसेंट अपना कोटा उठाया है । अगर इन सरकारों से तुलना करके देखें तो राजस्थान सरकार ने अपना काम बेहतर किया है । अगर बीपीएल गेहूं की बात करें तो बीपीएल गेहूं वह गेहूं है, जिसके लिए राज्य सरकार ने कई बार केन्द्र सरकार को लिखा है कि इसके रेट कम कर दिए जाएं ताकि जो चयनित परिवार हैं उनको सस्ते रेट पर यह गेहूं दिया जाए, लेकिन केन्द्र सरकार ने अभी तक उनकी बात नहीं सुनी । इसके अलावा बीपीएल गेहूं जो उठाया गया, उसकी स्थिति यह है कि राजस्थान की सरकार ने 75 परसेंट अपना उठाया, जबकि गुजरात सरकार ने 47 परसेंट उठाया, झारखंड सरकार ने 40 परसेंट उठाया और उत्तर प्रदेश की सरकार ने 27 परसेंट उठाया है । यह स्थिति है । फिर क्यों राजस्थान सरकार को लच्छेदार भाषण देकर बदनाम किया जाता है कि राजस्थान की सरकार गेहूं नहीं उठा रही है ?

सभापति महोदय, इतना भयंकर अकाल का संकट पहले कभी नहीं हुआ । सदियों से कभी नहीं सुना कि इस तरह का अकाल देश के अंदर कभी हुआ भी है । राजस्थान के जिस एरिए में पानी हुआ करता था, आज वहां ट्यूबवेलों का पानी नीचे चला गया है, हैंडपंपों का पानी नीचे चला गया है । पीने का पानी, जो हैंडपंपों से, नल योजनाओं से दिया जाता था, आज वह नल योजनाएं फेल हो गई हैं, वहां पानी नहीं है । हैंड पम्प हैं नहीं, ऐसी दयनीय स्थिति बन गई है, सभापति महोदय । जिस जिले से मैं आता हूं उस जिले में कभी पीने के पानी का संकट नहीं हुआ करता था लेकिन अब की बार अभी से भयंकर संकट बन गया है, अभी तो ये बरसात के ही दिन हैं । अभी दीवाली पर मैं जब गांव में था, उस दिन करीब 50 गांवों के लोग मेरे पास आए और वे कह रहे थे कि हमारे गांव में टैंकर से पानी भिजवा दीजिए, टैंकर की व्यवस्था कर दीजिए क्योंकि और तो कोई व्यवस्था है नहीं । सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज यदि टैंकर से पानी की व्यवस्था करेंगे तो जून के महीने में, जब भयंकर गर्मी पड़ती है, उस वक्त की क्या स्थिति होगी । मेरा कहना है कि केन्द्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए । केन्द्र सरकार पीने के पानी के लिए, राजस्थान के सूखे के लिए यदि कोई स्थायी योजना बनाती है, राजस्थान हमेशा सूखाग्रस्त रहा है, इसलिए ऐसी कोई योजना बने ताकि वहां के लोगों को सूखे से छुटकारा मिल सके, लोगों को अकाल की मार से छुटकारा मिल सके, केन्द्र सरकार को ऐसी कोई स्थायी योजना बनानी चाहिए ।

कल देश के प्रधान मंत्री जी लोक सभा में कह रहे थे कि नदियों को जोड़ा जाए, मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि नदियों को जोड़ने का प्लान तो आपका बनता रहेगा, आप राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर को नेशनल प्रोजेक्ट बनाएं । राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, जितना पैसा आप देते हो उस पैसे को ही वह खर्च कर पाती है, इसलिए इंदिरा गांधी नहर को आप नेशनल प्रोजेक्ट बना दें जिससे राजस्थान के कम से कम 1/3 भाग में तो पानी जा सकेगा और दूसरे यदि आपने इसे नेशनल प्रोजेक्ट बना लिया तो यह जल्दी तैयार हो जाएगी और दस साल के अंदर उन जिलों में पानी चला जाएगा । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यदि आप राजस्थान का भला चाहते हैं और राजस्थान के सूखे से छुटकारा चाहते हैं तो राजस्थान नहर को नेशनल प्रोजेक्ट में आप पूरा कीजिए और इसको नेशनल प्रोजेक्ट बनाकर राजस्थान को पानी दीजिए ।

सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के बारे में अखबार और इलेक्ट्रानिक मीडिया वालों ने मिलकर एक बड़ा भयंकर षडयंत्र किया है। यह बताया गया है कि 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर भूख से लोगों की मृत्यु हो गई है और इसका बड़ा प्रचार किया गया, जबकि वास्तविकता इससे परे है । इन 12 डिस्ट्रिक्ट में भूख से मृत्यु नहीं हुई है, केवल बीमारियों के कारण मृत्यु हुई है । लेकिन राजस्थान सरकार को बदनाम करने के लिए कि राजस्थान सरकार अकाल दूर करने के लिए काम नहीं कर रही है, राजस्थान सरकार को बदनाम करने के लिए यह षडयंत्र रचा गया और इसका जगह-जगह प्रचार किया गया । हमारे केन्द्र सरकार के खाद्य मंत्री ने कुछ अधिकारी भेज दिए, राजस्थान सरकार को पता ही नहीं कि कोई अधिकारी जांच करने के लिए आए हैं । ऐसा कभी होता नहीं है, राज्य सरकार को सूचना दी जाती है लेकिन राजस्थान सरकार को सूचना नहीं दी गई और यहां से अधिकारी गए । अब उनकी क्या रिपोर्ट थी, क्या नहीं थी, कैसे उन्होंने रिपोर्ट दी । केवल लोगों से बात करके आ गए, जबानी बात सुनी और जबानी बात के आधार पर यह रिपोर्ट दे दी कि लोग भूख से मर गए,

जबकि वास्तविकता कुछ और है । राजस्थान के लोकल अखबारों में, वहां "दैनिक भास्कर" एक लोकल अखबार है, उसमें 10 अक्तूबर को एक खबर प्रकाशित हुई कि किशनगढ़ में कुपोषण से 3 बच्चों की मौत हो गई। 17 अक्तूबर को 12 बच्चों की मौत की खबर "हिन्दुस्तान टाइम्स" में आई । यह खबर प्रकाशित होने के बाद वहां के प्रशासन ने, वहां की सरकार ने इसकी जांच के लिए राजकीय चिकित्सालय, कोटा के तीन वरिष्ठ डाक्टरों की एक कमेटी भेजी कि जांच करके बताइए कि वास्तविकता क्या है । इस कमेटी में जांच करने वाले डाक्टर मेडिसिन के भी थे, शिशु रोग विशेषज्ञ भी थे, पीएसएम, इन तीन आदमियों की कमेटी ने रिपोर्ट दी कि मौत भूख से नहीं हुई, इन बच्चों की मौत बीमारी से हुई है । संभावित बीमारियां थीं - पेराकानाइटिस, कम्पलिकेटिड मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया आदि, जो गांवों में होती रहती हैं, लेकिन एक राजनीतिक उद्देश्य के कारण हमारे केन्द्र सरकार की मंत्री, जिनके लोक सभा क्षेत्र में इस प्रकार की घटना हुई, वे चार-चार बार वहां से लोक सभा की मैम्बर बनीं, वे क्या कर रही थीं ? केवल टी.वी. वालों को वहां ले जाकर और अखबार वालों को वहां ले जाकर सरकार के खिलाफ गलत प्रचार हो रहा था और उनका हित करने के बजाय दुष्प्रचार किया जा रहा था और उन मौतों का महिमामंडन हो रहा था । उनमें कई मौतें ऐसी थीं जो सुसाईड केसेज थे लेकिन उन्हें भी भूख से हुई मौत करार दे दिया गया । इस प्रकार का वातावरण वहां बनाया गया । इसकी शिकायत गवर्नर को की गई । तब गवर्नर ने राज्य सरकार से इसकी जांच के लिए कहा और राज्य सरकार ने गृह सचिव की एक कमेटी भेजी जिसने कल ही अपनी रिपोर्ट दी है कि वहां भूख से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि बीमारियों की वजह से मृत्यु हुई है ।

हम अपने दूसरे साथियों से भी यह चाहते हैं कि राजस्थान की इस भीषण समस्या के लिए वे केन्द्र सरकार पर दबाव डालें कि वह इस भीषण संकट के समय ज्यादा से ज्यादा मदद राजस्थान सरकार को दे । मंत्री महोदय ने यह बताया कि राजस्थान के अंदर अकाल की...(व्यवधान)...

श्री सभापति : मीणा साहब, मेरी बात सुन लीजिए कि आपकी पार्टी को एक घंटे का समय मिला है और आपकी पार्टी की ओर से 4-5 स्पीकर हैं ।

श्री मूल चन्द मीणा : नहीं, हम केवल 2 स्पीकर हैं ।

श्री सभापति : नाम तो ज्यादा दिए हुए हैं । आपको बोलते हुए करीब 15 मिनट हो चुके हैं। अब आप अपनी पार्टी का समय खा रहे हैं ।

श्री मूल चन्द मीणा : महोदय, मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगा । राजस्थान की सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए मांगे थे लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार ने एक पैसा तक नहीं दिया है । राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से 56 लाख टन गेहूं मांगा है लेकिन अभी तक केवल 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं मिला है जो राज्य सरकार ने उठा लिया है। इसके अलावा और 5 लाख टन गेहूं देने की बात है । इससे काम कैसे चलेगा ? यह तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है ।

सभापति महोदय, राजस्थान में इतना भयंकर अकाल है कि लोगों को रोजगार देने और मजदूरी देने के लिए वहां की सरकार के पास पैसे नहीं हैं । ऐसे समय में केन्द्र सरकार इस मामले को और डिले कर रही है । मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की टीम वहां कब

गई और कितने दिनों के बाद उस टीम ने रिपोर्ट दी ? केन्द्र सरकार की वह कौन सी कमेटी थी जिसने इस पैसे को रिलीज़ नहीं किया, इस अनाज को रिलीज़ नहीं किया ?

सभापति महोदय, आप राजस्थान से आते हैं और आप राजस्थान के दु:ख-दर्द को समझते हैं । आप स्वयं राजस्थान गए थे और आपने वहां कहा था कि राजस्थान की जनता को इस भीषण अकाल से छुटकारा दिलाने के लिए कोई भी सरकार हो, चाहे वह केन्द्र में हो, चाहे वह राजस्थान में हो, मैं उस सरकार से विशेष आग्रह करूंगा कि वह यहां के लोगों की ज्यादा से ज्यादा सहायता करे । मैंने अखबारों के माध्यम से पढ़ा है कि आपने उसी भावना से प्रेरित होकर अपने यहां कैबिनेट मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाई थी और उनसे कहा था कि जहां भयंकर अकाल है, उन ऐरियाज़ के लिए वे एक पैकेज जारी करें । आप हमारा दु:ख समझते हैं । आपने राजस्थान का नेतृत्व किया है । आपने अकाल को देखा है । अकाल में लोग कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, यह दिल्ली में रहने वाले लोगों को पता नहीं है। अकाल कैसा होता है, अकाल के समय क्या समस्या होती है, इसे आप जानते हैं । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने प्रभाव का उपयोग करें और राज़स्थान को ज्यादा से ज्यादा सहायता दिलवाएं ।

सभापति महोदय, जो लोग राजस्थान की सरकार के ऊपर इस तरह के ब्लेम आदि लगाते हैं, वे उन गरीबों के हितैषी नहीं हैं, वे तो उनके हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं । मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने सितंबर के महीने से अकाल के कार्य खोल दिए हैं जिसके तहत लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और गांव-गांव के अंदर ग्राम पंचायतों के पास 10-10 क्विंटल गेहूं रखवा दिया गया है ताकि कोई व्यक्ति भूख से न मरे। यदि ग्राम पंचायत, हैडक्वार्टर से एक किलोमीटर से दूर है तो उसके लिए 2 क्विंटल गेहूं रखवा दिया गया है । राजस्थान सरकार की व्यवस्थाओं को देखकर अगर केन्द्र सरकार ने पूरा सहयोग दिया तो इस संकट का निवारण करने में राजस्थान की सरकार पीछे नहीं रहेगी, इस मौके पर मैं यही कहना चाहता हूं । धन्यवाद ।

श्री सुनील शास्त्री (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। अभी हमारे साथी सांसद कह रहे थे और उन्होंने अपनी बातों में आरोपों की ज्यादा बात की तथा केन्द्र सरकार पर आरोप लगाए और जो हकीकत है, जो सही बात है उसका आकलन उन्होंने कम किया, बल्कि उन्होंने इस बात को ज्यादा दर्शाया कि किस तरह से केन्द्र सरकार विफल रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम एक ऐसे सदन में, सर्वोच्च सदन में बैठे हैं और यहां से जब हम कोई भी बात कहते हैं, कुछ भी यहां प्रस्तुत करते हैं तो सारा देश हमारी ओर देखता है। मेरा यह मानना है तथा यहां पर मेरे सभी सम्मानित सदस्य यह मानेंगे कि सूखे की यह जो स्थिति है वह केवल किसी एक पार्टी या किसी एक दल से जुड़ी हुई नहीं है बल्कि सूखे की स्थिति से पूरे राष्ट्र को निबटना है और यहां पर मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं तथा विशेष बल इस बात पर इसलिए दे रहा हूं कि आज जिस प्रकार से सूखे की स्थिति से निबटने के लिए इस विषय का राजनीतिकरण किया जा रहा है यह बिल्कुल गलत बात है। आज हमें पार्टी लाईन से ऊपर उठकर इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालना होगा। मेरा यह पूरा विश्वास है कि जिस तरह से केन्द्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में इस ओर विशेष ध्यान दिया है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते उसके द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अगर आज हम कहें कि नेशनल केलेमिटी कन्टींजेंसी फंड की जो बात है, पांच सौ करोड़ रुपए के कोरपस फंड की जो बात है यह सब

हमारी सरकार ने, एन0डी0ए0 की सरकार ने ही इस ओर कदम बढ़ाया, इस ओर ध्यान दिया। अभी बहुत सी बातें कही गईं कि भेदभाव की राजनीति है। मैं कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी किसी प्रकार से अगर कहीं कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा सामने आई तो केन्द्र सरकार ने कभी भी किसी प्रकार से भेदभाव की राजनीति नहीं अपनाई, ऐसी रणनीति नहीं अपनाई। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे पश्चिमी बंगाल के सांसद भी यहां पर बैठे हैं। आपको याद होगा कि जब पश्चिमी बंगाल में बाढ़ की स्थिति आई तो इसी सरकार ने तुरन्त 460 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की। यही नहीं मैं यह बताना चाहता हूं कि आज ...(**व्यवधान**)...

आप देखें 460 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित हुई है। ...(**व्यवधान**)...

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल): 460 को 1460 कर दीजिए ...(**व्यवधान**)...

श्री सुनील शास्त्री : मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, my humble submission is that this is not a public relations exercise which is going on. This is a very serious discussion on drought. Let us discuss that. ...(*Interruptions*)...

SHRI SUNIL SHASTRI: I am discussing a very serious matter. ...(*Interruptions*)....

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: You are doing a public relations exercise for the Government of India. The Ministers of the Government of India are there. ...(*Interruptions*)...

SHRI SUNIL SHASTRI: When I am saying something, I request the hon. Member to believe me because it is a fact. I am not saying anything wrong. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: You are not the Government of India. The Government of India is there. ...(*Interruptions*)....

श्री सभापति : आप बोलने दीजिए। जब आपकी पार्टी का या आपका अवसर आए तब बोलिए।

श्री दीपांकर मुखर्जी: सरकार की तरफ से बोलें, सरकार के मंत्री बोलें। ...(**व्यवधान**)...सूखे के ऊपर बातें करिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : सरकार की तरफ से बोलें या अपनी तरफ से बोलें। आपका बोलने का अवसर है। उस अवसर के समय यदि आप इन चीजों का खंडन करेंगे तो लोग सीरियसली आपको सुनेंगे। ...(**व्यवधान**)...

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): The hon. Member should read it out.

SHRI SUNIL SHASTRI : You want me to read out that particular

part? I will certainly read it out, because it is a fact. I am not saying anything which is not correct. I will only speak the truth, and I will only present before you the fact.

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां पर इस बात को कहना चाहूंगा कि जो कमियां किसी सरकार की रही हैं, प्रदेश सरकार की रही हैं तो आज उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। अभी हमारे माननीय सांसद महोदय राजस्थान की बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल डाली गयी थी, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जितना अनाज केन्द्र ने राजस्थान सरकार को ऑफर किया, राजस्थान सरकार को दिया, उसे राजस्थान सरकार उठाने में सक्षम नहीं रही। मैं आपको बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसी प्रकार से किया है। जो अनाज उसे आबंटित हुआ, उसे उसने उठाया नहीं।

जहां तक क्रॉप इन्श्योरेंस का सवाल है, मैं राजस्थान के माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि क्यों नहीं क्रॉप इन्श्योरेंस स्कीम को राजस्थान सरकार ने उस खूबी से लागू किया जिसकी अपेक्षा राजस्थान के लोगों ने की थी, जैसी आशा राजस्थान के किसानों ने सरकार से रखी थी। मैं इन सब बातों को इसलिए कह रहा हूं कि हमें राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। आज सूखे की स्थिति है, एक गंभीर स्थिति है, 15 करोड़ से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को मिलजुलकर इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालना होगा।

मैं आज राजस्थान की ही बात लेता हूं। जिस समय इन्दिरा गांधी कैनाल का प्रस्ताव था, उस समय लोगों का यह मानना था, लोगों का यह कहना था कि इससे कुछ नहीं होगा और यह केवल एक योजना ही बनकर रह जायेगी। लेकिन आज मैं इस बात को गर्व के साथ कह सकता हूं कि इन्दिरा गांधी कैनाल राजस्थान में जहां-जहां से गुजरी है, वहां पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने जिस बात का जिक्र किया है, उससे आप सब अवगत हैं। हमारे सम्मानित व्यक्ति जो सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, डा0 के0 एल0 राव, उन्होंने इस बात को बहुत पहले देश के संज्ञान में लाने का प्रयास किया था। वह चाहते थे और उन्होंने यह कहा था कि एक गारलैंड कैनाल द्वारा, रीवर्स को जोड़ने की जो स्कीम है, उसको हम लोग लागू करें। उनका विचार था कि वैस्ट से साउथ की अगर सब नदियां एक साथ जोड़ी जाती हैं और उसके पश्चात कैनाल बनाये जाते हैं और अलग-अलग स्थानों पर पानी को पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो बाढ़ और सूखे का जो प्रकोप आता है उससे हम अपने किसानों को और अपने देश को बचा सकते हैं। हम लोग हमेशा गर्व से कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। मेरे पूजनीय पिता लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस देश को "जय जवान, जय किसान" का नारा दिया था। उनका यह मानना था, उनका ही नहीं देश के हर एक नागरिक का यह मानना था कि आज सीमाओं पर हमारी रक्षा, देश की रक्षा हमारे बहादुर जवान करते हैं, तो देश के अंदर भुखमरी के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ता है तो वह हमारा बहादुर किसान है जो अपना पसीना बहाकर हम लोगों को अन्न देता है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि जब आज हम अपने देश को कृषि प्रधान कहते हैं तो आज पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, ये दो-तीन प्रदेश ऐसे हैं जहां पर हमने किसानों के उत्पादन को बढ़ाया है जिसके कारण उपज बढ़ी है। सभी नदियों को जोड़ने की बात हमारे प्रधान मंत्री जी ने अभी हाल ही में कही है। मैं मानता हूं कि अगर इस योजना की ओर पहले से ध्यान दिया गया होता तो आज जो स्थिति हमारे देश में उत्पन्न हो जाती है, उससे हम बच सकते थे, उसका हम

सामना कर सकते थे । आज आवश्यकता है कि हर पार्टी के हर व्यक्ति को इस पर सोचना होगा कि जो आज हमारा गारलैंड इनलैंड रियर सिस्टम या कैनाल सिस्टम जोड़ने की जो योजना है, इसको हम एक स्वरूप दें, इसको बनाने की चेष्टा करें । बहुत से लोगों का कहना है कि इसमें बड़ी धनराशि लगेगी लेकिन आज अगर आप देखें कि हमने जिस प्रकार से देश को नेशनल हाइवेज़ से जोड़ने का प्रयास किया है, जिस तरह से हमें उसमें सफलता मिल रही है, उसमें धनराशि की कमी जरूर थी लेकिन हमने रिसोर्सिज़ को डैवलप किया रिसोर्सिज़ को किसी तरह से जैनरेट किया और आज हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं । ठीक उसी प्रकार से अगर आज हम सब नदियों को जोड़ने की बात करेंगे तो जहां एक ओर हमारी नदियों के माध्यम से हम सूखा और बाढ़ दोनों को ही रोक सकेंगे वहीं किसानों को सिंचाई का जो एक साधन है, उसे हम सही तरीके से उन्हें उपलब्ध करा सकेंगे । उसके साथ ही साथ जो आवागमन की सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हमें मिल जाएगी, वह भी बड़ी भारी उपलब्धि इस दिशा में होगी । महोदय, फर्टीलाइज़र्स पर हम लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया । यहां पर केन्द्रीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनके सामने इस बात को रखना चाहूंगा कि हमने फर्टीलाइज़र पर काफी ध्यान दिया लेकिन सही मायने में अगर आप विश्व के अन्य मुल्कों को देखें तो आपको वहां पर यह देखने को मिलेगा कि ओरिजनल जो खाद होती थी, गोबर की खाद, उसका आज ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है न कि फर्टीलाइज़र्स का । मेरा कहना है कि फर्टीलाइज़र वगैरह की जो सुविधाएं हमने दीं, जिस समय आवश्यकता थी, उस समय ज्यादा विचार न करते हुए हम उस ओर बढ़े लेकिन आज आवश्यकता यह है कि ऑरगैनिक जो साधन हैं, जो हमारे पुराने साधन हैं, गोबर की खाद है, अन्य खाद है, उसका प्रयोग हम अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करें जिससे हमारी उपज भी बढ़े । माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से, आपके माध्यम से इस बात को यहां पर कह रहा हूं और बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि आज अगर यह कहा जाए कि बीमारी के कारण किसी की मृत्यु हुई जब कि भूख के कारण मृत्यु हुई हो तो यह जायज़ बात नहीं होगी, यह सही बात नहीं होगी । श्रीमन्, मुझे जानकारी मिली है कि पार्लियामेंटरी कमेटी भी वहां गयी थी और राजस्थान में उनके भी कुछ लोगों ने इसी बात पर विशेष ध्यान दिलाया कि भूख के मारे लोगों का देहांत हुआ है । मैं इसलिए इस बात को यहां पर कह रहा हूं, इसलिए इस बात को सामने ला रहा हूं कि अगर अपना कोई बच्चा मरता है, अगर आज हमारे नेता लोग जाकर वहां कहें या कोई व्यक्ति वहां पर जाकर कह दे कि यह तो बीमारी के कारण मृत्यु हुई है तो मैं समझता हूं कि हम जनता के बीच विश्वास खो देंगे । मैं यहां पर यह बात कहना चाहता हूं......

श्री मूल चन्द मीणा : महोदय, संसदीय कमेटी तो वहां गयी ही नहीं है । आप गलत कह रहे हैं।

श्री सुनील शास्त्री : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जिसके बच्चे मर रहे हैं, जिस परिवार में लोग भूख से मर रहे हैं, अगर उनका यह कहना है कि हमारे लोगों का जो निधन हुआ है, वह भूख से हुआ है, भूख के कारण हुआ है तो आज हम सबको उस बात को मानना चाहिए । प्रदेश सरकार अगर कहे कि वह नहीं मानती तो मैं समझता हूं कि यह उनका गलत बयान है, उनकी गलत सोच है । आज हमें मानना चाहिए और हमें इस दिशा में कठोर कदम उठाने चाहिए । हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए जिसके माध्यम से हम भुखमरी .....

डा0 अबरार अहमद (राजस्थान): सभापति महोदय, मैं माननीय.....

श्री सभापति : आप बाद में बोलिएगा । आपका नम्बर आ रहा है ।

डा0 अबरार अहमद : मेरा नाम उसमें नहीं है, मैं केवल एक बात इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं ।

श्री सभापति : कह देना पर अभी ठीक नहीं रहेगा ।

डा0 अबरार अहमद : माननीय सांसद जो भूख से मरने वाली बात कह रहे हैं, यह सब सुनी सुनाई बात है। अगर इस सदन से वहां कोई गया है तो सिर्फ मैंने अपनी आंखों से देखा है और यह वीडियो रील मेरे पास है । जिनके बच्चे मरे हैं, पूरे गांव में 9 बच्चे हैं, उन नौ बच्चों के माता-पिता ने पूरे गांव के चौपाल में कहा है कि किस बीमारी से मरे हैं, कितने दिन अस्पताल में इलाज कराया है, कितना पैसा खर्च किया है । मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सभा पटल पर इस वीडियो कैसेट को रख सकता हूं और इसको वह देख सकते हैं । मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं ।

श्री सभापति : *देखिए, आप बहुत लंबे अर्से से पार्लियामेंटेरियन रहे हैं । जब तक मैम्बर कंसीड न करें तब तक आपका इंटरवीन करने का कोई राइट नहीं बनता ।*

श्री सुनील शास्त्री : माननीय सभापति जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां पर माननीय सदस्य गए होंगे, अगर वहां पर कहा है तो मैं इनकी बात से इंकार नहीं करता लेकिन कई जगहों पर ऐसे लोग गए हैं जिन्होंने वहां पर बातचीत की है, वहां पर माता-पिताओं ने यह कहा है कि भूख के कारण हमारे परिवार में निधन हुए हैं । मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि हम यह नहीं कहते कि कहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है लेकिन यह बहुत ही गंभीर समस्या है ।

श्रीमन्, अगर आज हमारे स्वतंत्र भारत में लोग भुखमरी के शिकार हों, आज भूख के कारण लोगों का निधन हो तो यह बहुत ही शर्म की बात है और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि यह दायित्व अगर हम समझते हैं कि केवल सरकारों का है तो वहां पर भी हम गलत सोचते हैं । आज यह दायित्व हम सब का है । हम सबको मिलकर इस समस्या के विरुद्ध एक कठोर कदम उठाना होगा, लड़ाई लड़नी होगी और तभी यह संभव होगा कि भुखमरी के कारण जो हमारे लोग मरते हैं, उनको हम बचा सकेंगे । श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए माननीय सदस्यों से यही आग्रह करूंगा कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालें और एक ऐसा रास्ता बनाएं जिसके माध्यम से हम देश में हरियाली और खुशहाली ला सकें ।

श्री सभापति : श्री सी. रामचन्द्रैया, बोलिए । ......इससे पहले कि आप बोलें, मैं सभी सदस्यों से एक निवेदन करना चाहूंगा । सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के नेता यहां पर हैं । मसला बहुत गंभीर है लेकिन हाऊस में माननीय सदस्यों की उपस्थिति बहुत कम है । इससे एक मैसेज जाता है कि ऐसे गंभीर मसले पर पार्लियामेंट चिंतित नहीं है । इसलिए मैं सदन के सत्ता पक्ष, विरोधी पक्ष और बाकी सभी दलों से निवेदन करना चाहूंगा कि ...**(व्यवधान)**...

श्री लालू प्रसाद (बिहार): छोटे दल वाले लोग बैठे हैं । प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कोई यहां नहीं है और हुक्मदेव नारायण यादव जी को भेज दिया गया है यहां पर ।

श्री सभापति : यादव जी को भेज दिया है और आप यादव जी की बात कर रहे हैं ? इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता लेकिन सदन को इसे सीरियसली लेना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य इस चर्चा में भाग लें । भाग लेने के बाद कम से कम यह मैसेज तो पब्लिक में जाता है कि हमारे संकट के प्रति सदन को सहानुभूति है ।

SHRI C.RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on a very important subject. Drought, which is occurring in this country very frequently, and not a single session had passed without discussing this subject. Sir, it is needless to mention that farming community is the most neglected community in this country. The seats of Members of this House might have changed; there might have been a change in their positions; a number of Committees in this regard might have been set up by the various Governments successively. And, a lot of heat might have generated during these debates; a number of packages should have been announced by the Government and implemented to their capacities. Thousands of crores of rupees should have been spent on these schemes, but one thing remains static, that is, the miserable condition of the Indian farmer. Sir, it is undoubtedly, I should say, it is the failure of the governance of this country for the past five decades. We have failed on the irrigation front; we have failed in harnessing the waters of the perennial rivers in this country, we have failed in predicting the drought and its impact on the economy and in initiating effective measures to combat the drought and when there is massive calamity, we get to hear about the agonising conditions of the farmers in this country. A number of times we have expressed our agony both inside and outside the House regarding the miserable plight of the Indian farmers. Sir, if you go through the data, today only 39 per cent of the net sown area is irrigated in this country. This was admitted by the hon. Prime Minister in the Lok Sabha yesterday. And, for the past two-and-a-half to three decades, no significant and constructive efforts have been made to build agriculture infrastructure in this country. Most of the farming community has to depend on ground water, and there is a tremendous pressure on this. And the country's hydraulic system is heavily dependent on monsoons. But since we could not protect the environment, initiate measures for sustained development by preserving environmental conditions of the country, there have been erratic monsoons which are playing havoc with the farmers, but also with the economy of the country. The public investment in irrigation has fallen drastically from 23 per cent in the First Plan to eight per cent in the Eighth Plan in real terms. And, I am told that it is seven per cent now. Sir, I have gone through the document of the Tenth Plan. It has to

accommodate a spill-over of 159 major irrigation projects and 242 medium irrigation projects, which had been targeted for the earlier years. Sir, the need of the hour is to provide more funds for irrigation infrastructure in this country. The drought has its impact both on agriculture and industry. There will be persistent stagnation in domestic savings and investments, and there will be a severe deterioration of fiscal positions both at the Centre and in the States which erode the resilience of the economy of the country. That is what is happening and this makes it very difficult to withstand the impact of drought in this country. Sir, I had the privilege of speaking on a similar subject earlier also. I made this point very clear that you must improve the productivity of the farmers as well as the productivity on the industrial front. Our productivity even on the industrial front is very, very poor compared to other developing countries; I am not mentioning of the developed countries like Europe and China. When more than 70 per cent of the people still depend on agriculture, -- ours being primarily an agrarian economy -- the more the income of the rural masses, the more would be the capacity to purchase goods; there will be an increased demand for goods. And, when we invest our savings in the industrial field, the industry will get benefited and there will be a greater demand for goods, and the industry can generate, manufacture, the goods. That is the way in which we have to re-invigorate the country's economy and that is where agriculture plays a vital role in this country. A number of times I have re-asserted this fact. But, unfortunately, the purchasing power of the farmers of this country is considerably going down; of course, thanks to the efforts of the Government, they could keep the inflation level static to a certain extent. That is a solace to the poor people of this country. And because of this lower demand for the goods, the industrial growth has also been affected.

Sir, I would now mention about the State of Andhra Pradesh from which I come. The failure of the monsoon in our State has been more accentuated by the inaction of the Central Government, without any timely help. And they have failed to assess the impact of this drought and assess the situation in the State. The deficiency of rainfall in our State is more than 47 per cent. We have got very favourable agro-climatical conditions in our State. We have got the very fertile Godawari Basin and the Krishna Basin where we can produce more paddy. This year, out of 81.8 lakh hectares, which is the normal crop area during kharif, we were able to cultivate only 32.33 lakh hectares. Even in that area, we could not save the crops because of shortage of water. Out of 1126 mandals, 836 mandals have

been declared as drought-affected areas. Sir, I am extremely unhappy over the attitude of our neighbouring States. I would plead that there should be a national spirit among all the States. The entire delta in our State, which is around 81.8 lakh hectares, has been affected, due to lack of water. We have requested the Government of Karnataka because there is sufficient water in the reservoirs of Krishna delta, like Alamatti. They don't need that much quantity of water. There is water in the Cauvery; they do not need that much water. On the other hand, we need water, and that is why we made a request to the Government of Karnataka to release water for saving our crops. Whatever power is generated from the water released by them, we are prepared to give it to them.

SHRI M.V. RAJASEKHARAN (Karnataka): Sir, the fact is that...*(Interruptions)*....

SHRI C. RAMACHANDRAIAH : I am not yielding, Sir. I have a lot of respect for Shri Rajasekharan, but I am not yielding. ...*(Interruptions)*.... I am sorry, Sir. When he gets an opportunity to speak, he can put forth this point. ...*(Interruptions)*....

SHRI M.V. RAJASEKHARAN : Sir,...

MR. CHAIRMAN: Please take your seat now...*(Interruptions)*...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH : Sir, I am not yielding. I am only pointing out the callous attitude on the part of our neighbouring State. In contrast, we can proudly say that when there was a cyclone which devasted the economy of Orissa, we were the first to go to the rescue of Orissa. We sent our team. We sent rice, blankets, medicines etc. and we restored the communications system in Orissa. That is the spirit we have maintained. So we did not expect this sort of treatment from our neighbouring States. Being a lower riparian State, Sir, we cannot be punished. Of course, you are entitled to retain that water.

DR. M.N. DAS (Orissa): Sir, it was from Andhra Pradesh that Orissa got the first supply of relief material during the super cyclone, and not from Tamil Nadu.

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH : What I am trying to say is that States should be ready to share the distress of their neighbours. That is

the national spirit. This is the meaning of federalism. There is no point in making the accusation that a particular State is getting more, and another one is getting less. We do not object to Rajasthan getting more and Karnataka getting more. But, it is our primary duty to fight for our State's cause that is why we have been representing at various fora and trying to solve our problems. We have passed a Resolution unanimously. The Congress is also a signatory to that Resolution. We have sent the Resolution to the Government of India that we require Rs.1210 crores. The Government of India has not been that considerate. They have given only Rs.170 crores, which is a paltry amount. I have got my own apprehensions, because of the statements made by the leader of the Congress.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (DR. MANMOHAN SINGH): The Congress had never said Andhra Pradesh should not get its due. Please don't misquote us.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH:There was a reference at Mt. Abu also, regarding Andhra Pradesh. Yesterday, in Parliament also.. ...*(Interruptions)*... If you want I can quote it.

SHRI K.RAHMAN KHAN (Karnataka): That is different. It has nothing to do...*(Interruptions)*...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Yesterday also...*(Interruptions)*... I can quote, if the Chair permits me ...*(Interruptions)*... Sir, there is a clear difference between what they have done for States like Andhra Pradesh and what they are doing for Rajasthan. ...*(Interruptions)*... This is the statement made by Madam Sonia Gandhi. ...*(Interruptions)*.... Sir, should I read out the statement made at Mt. Abu?

DR. MANMOHAN SINGH: We are saying that Rajasthan should get its share. We are not...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Yes. We do not have any objection to Rajasthan getting its share because Rajasthan is also facing problems like suicides by farmers, severe drought and so on. We know what is meant by drought more than anybody else in the country. We share the distress conditions of the other States. We share their feelings. At the same time, you should not come in the way of Andhra Pradesh getting more funds and more resources. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. S. AHLUWALIA (Jharkhand): Let him speak. We have not disturbed you.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, I request that I should be compensated for the time taken by these interruptions. The more the disturbance, the more the time. ...*(Interruptions)*...

Sir, we have requested for Rs.1200 crores and 25 lakh tonnes of rice for rehabilitating the affected people in our State. Sir, there is one programme which has been...

MR. CHAIRMAN: Your time is over.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: I think I have been given 14 minutes, Sir. Anyway, I am finishing.

The need of the hour for the Government of India is to take a holistic approach. The Government should lay more emphasis on water harvesting, water conservation and alternate cropping. Alternate cropping has to be undertaken on a war-footing. The farmers have to be motivated and they have to be encouraged to grow cereals like bajra, maize and so on, which consume less water and which increase the income. In this, Government participation, which has been totally absent, should also be there.

Sir, I appeal to all the political parties that in times of natural calamities, we should not politicise these issues. We must try to reach a consensus for the solution of these problems. In this regard, I welcome the proposal for linking the rivers, that has been announced by the hon. Prime Minister yesterday. It has a very wide perspective, that involves work over the next forty or fifty years. There are certain perennial rivers in the North and certain non-perennial rivers in the South. If this linking is done, most of the States which do not have water will be benefited.

Sir, ultimately, agriculture in India has to be made a viable profession. It is not a viable profession at present, because of small landholdings. Because of the implementation of land ceiling laws, the extent of landholding of the common man has gone down. The productivity is also very low, because of which agriculture has become a totally unviable profession. There is a necessity to increase the productivity. Even today, 49 per cent of the urban poor and 41 per cent of the rural poor are still under-nourished.

3.00 P.M.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Yes, Sir. They consume 25 per cent less calories than what they should have consumed, on an average. There is a demand for foodgrains; there is a surplus in our godowns. But the people do not have access to the foodgrains. The Government should come forward and provide that access to farmers so that the people are in a position to purchase the foodgrains. The Government's endeavour should be to increase the productivity and reduce the cost of inputs in agriculture so that the viability of agriculture, as a profession, is increased. Ultimately, I have a request to the Government of India, that is, it should provide more funds for the rehabilitation of the victims of drought in our State. I request specifically for provision of more funds for drinking water in our State.

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN (Kerala): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak. Sir, we are discussing a very serious problem which is affecting almost 14 States of the country and which is unprecedented in the history of the country. Sir, this year there has been a sharp decline in the rainfall and we had a very bad monsoon. The rain deficit has been about 30 per cent. In July itself, it was 49 per cent. Naturally large parts of the Central and the Western India have been suffering most from drought. Almost the whole country is facing the same problem. Sir, this kind of a tendency of drought has been there for the last three or four years. This year it is very acute. What would be its impact? Naturally, there would be a sharp fall in the agricultural production.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAMA SHANKAR KAUSHIK) in the Chair]

The area under cultivation is also going down. Last year it was 20 million hectares of land was there for cultivation of cereals. This year it has been reduced to 142 million hectares. So, what would be the result? There was drought in 1972, 1979 and 1987. According to the Government records, in 1972-73 the foodgrain production fell as much as by 7.8 per cent, the agricultural section has a whole was reduced by 5.7 per cent and the GDP growth turned negative to a .3 per cent. In 1979-80 the foodgrain production plunged by 17 per cent. As a result of this, the manufacturing sector also witnessed a fall of 3.4 per cent and the GDP growth was a negative of 5.2 per cent. Naturally, there would be an impact on our overall growth because of the sharp fall in the agricultural production which is being expected this year. So, the impact would be more not only on cereals but

also on the area of sugarcane cultivation of U.P. and Maharashtra which has been adversely affected by this drought situation. We are going through a new economic policy and because of this policy the agricultural input is being reduced due to lack of investment by the Government as well as the private sector. Mr. Ramachandraiah has already explained the details about the agricultural input from the side of the public sector. Naturally, they are expecting that the private sector is going to invest more in the agricultural sector. But what was the real effect? The private sector has never invested in agriculture for the benefit of the poor and medium peasants and the agricultural labour. This aspect should be taken note of. But this Government of BJP has never given any importance to increasing the input for agriculture, investing for irrigation and other such things which support the agricultural input. Naturally, because of this the result is before us. It was reported in 2001 that the availability of cereals in the country dropped to an all time low of less than 143 kgs. and that of pulses below 10 kilogms per head, a situation similar to colonial India.

That is the situation. The per capita income is coming down. This year, there is an unprecedented drought. We have discussed this matter even during the last Session of Parliament. The hon. Agriculture Minister was very serious on the situation. It was reported in *Frontline*. The report says, I quote, "The people who are likely to be the worst hit are the farmers and farm labourers. The only thing that can really help the farm labourers is a Food-for-Work Programme. And, here, the administrative machinery has an important role to play." This is what the hon. Agriculture Minister said. Again, he said, I quote, "I have heard of cattle being sold at low prices, because fodder prices have gone up. That is why a Food-for-Work Programme, fodder supply and cattle shelters are priority areas." These were the words of the hon. Agriculture Minister. He further said, I quote, "Even at our last meeting with State Ministers, the total requirement of foodgains that was put before us was only about 151 lakh tonnes. Availability is not a problem. The whole problem is reaching the farm labourers on time and giving them enough work." What a beautiful assessment made by the hon. Agriculture Minister! This issue of *Frontline* is dated 30th August, 2002. The Government was very serious about the situation. What have you done? What was the announcement from the Government? Different State Governments came out with suggestions on losses and reliefs and submitted the same to the Centre. The total relief asked for is Rs. 20,000 crores. This is the total amount requested by the States which the hon. Minister of Agriculture received in the month of

August, 2002. When did you announce the relief package of a meagre amount of Rs. 2,000 crores? This package was announced on 16th of November, 2002 - on the eve of the Winter Session of Parliament! You have announced this meagre amount of Rs. 2,000 crores just a day before the Winter Session starts! There were so many discussions. There was also a Committee headed by the hon. Deputy Prime Minister. I must say that the hon. Deputy Prime Minister was serious about the national security. His national security is only about the security against Pakistan in the border. That national security does not include the poorer sections living in the villages of the country. What kind of national security is it to think about when the poor people are starving in the country? What kind of national security is it minus the poor people in the country? What is the attitude of this Government? This Government is having such a callous attitude towards the poor people that it has failed to solve the problem of drought and the Government has never risen to the expectations of the people. Even the supporters of the Government are forced to oppose the Government. That is what is happening in this House. This is very tragic to say. Look at the problems of the poor farmers and the agricultural labourers. There is no package for agricultural labourers. The Task Force did not consider the waiver of interest on loans taken by the poor farmers and the medium farmers. How are they going to pay the interest? What is the position of farmers and agricultural labourers? Sir, starvation deaths are reported from Rajasthan, Orissa, Tamil Nadu and even from Kerala. I would like to quote from a newspaper report on the impact of drought. It was reported from Chhattisgarh. The report says, I quote, "Having mortgaged his small piece of agricultural land for the coming season to arrange for the money to perform the last rites of his parents, a 42-year old farmer, Dhiraj Suryavanshi, ended his life on October 14 after all his hopes of earning some money from the paddy crop crashed due to acute drought." This is the situation that is prevailing in almost all villages of India. Who is going to care about these poor people? What is the approach of the Government? The Government is not at all serious. Here, we are simply discussing the matter very peacefully. What is the approach of the B.J.P.? Sir, it was reported on 15th November, 2002, in a newspaper from Madhya Pradesh. The report says, I quote, "The Madhya Pradesh Assembly was repeatedly adjourned today and the entire day's business was washed out as Bharatiya Janata Party Members continued their tirade against the Government protesting in the well of the House against 'poor and inept' handling of the drought situation in the State."This is what has happened in Madhya

Pradesh. Shri Venkaiah Naidu does not know anything about it. He was repeating, preaching, telling and advising us how to behave in the House. This is the behaviour of the BJP in Madhya Pradesh! Had they been in the Opposition, Parliament would not have functioned at all.

Coming to the issue of agricultural labourers, I would like to say that the Public Distribution System has failed totally. We have more than 650 crore tonnes of grain in the godowns of the Food Corporation of India. But the Government has not come out with any concrete proposal to help the landless agricultural labourers, who are hit by the drought. You talk about giving some package to this State and that State. But, what is the package for the landless labourers? You are yet to announce it. You only talk about *'Antyodhaya'* and all that. What is the BPL or the APL situation in this country? People are dying, but according to your list, they are all above the Poverty Line. The number of people holding BPL cards is very limited. So, you have to come out with a concrete proposal for agricultural labourers who have lost their jobs, because of the prevailing drought situation in the country, rather than coming out with announcements that you have so far made. Therefore, a specific programme should be announced by the Government. While replying to the debate in the Lok Sabha on the prevailing drought situation in the country, the Prime Minister, or, the concerned Minister did not make any announcement. I hope, in this House, the Government will come with a specific proposal to help the landless agricultural labourers who have been affected by the drought situation prevailing in the country.

Then, Sir, with regard to crops, there is a different problem in my State. In Kerala, we have cash crops like coconut, rubber, spices, etc. These are all long-term crops. So, the loss will be for many years. If there is drought, the loss will not be for a short period, it will be for a very long period. It will be spread over three or four years. So, the loss will be more. The Government has not announced any special programme for the drought-affected areas; for such cash crops which have been adversely-affected by the drought.

Unfortunately, Sir, in Kerala, there is the Congress Government. They did not approach the Government with proper suggestions. And that Government is invisibly supported by the BJP. This is the advantage that the Kerala Government has. There is not just a Congress Government, but it is invisibly supported by the BJP. Even yesterday, there was an election for the post of Deputy Mayor, which was jointly fought by the Congress and

the BJP. Now, their candidate has been elected as the Deputy Mayor of Cochin. That is the advantage with Kerala. But, unfortunately, with regard to drought situation, sufficient help has not come from the Central Government. That is the situation.

Sir, with regard to irrigation and water supply, no specific programme has been announced so far. We have to save the wells, the natural resources and the aquifer of this country, in order to be able to face such a situation. Unfortunately, no such comprehensive plan has been announced by the Central Government.

Again, Sir, we are hearing about the much-hyped programme of connecting river waters. Even the small problem of distribution of the Cauvery river-waters has not yet been solved. We have not been able to resolve the water problem of Krishna and Yamuna. And now the Prime Minister is talking about connecting all the rivers of the country. This means there is going to be a plethora of problems and a new Pandora's box is going to be opened. This is the idea of the BJP. They want to destabilize the entire thing. They have a big dream. I am not opposing it. But where are the funds? Nearly rupees five to six lakh crores are needed for this. Unfortunately, the Government has not come out with any concrete proposals to assist the poor people. You have not come out with any concrete proposals for the poor people. I hope the Government will come out with concrete proposals. Sir, this is not a simple problem. For the poor people, every day there is drought in their life. To solve this problem, the Government must come out with some concrete proposals.

SHRI AIMADUDDIN AHMED KHAN (DURRU) (Rajasthan): Mr. Vice-Chairman, Sir, at the outset, I wish to express my gratitude to you for giving me the opportunity to participate in the discussion on the widespread drought that has affected the country this year. Some of the States like Rajasthan are facing drought for the fifth consecutive year. This year, in particular, the situation is the severest of all. Therefore, I would like to thank the hon. Chairman for taking special interest in drought relief measures, especially, in Rajasthan. It will help us in chalking out a strategy to tackle the drought situation in the State. I agree with both the Leader of Opposition and the Prime Minister, that we should not politicise this issue. It is, basically, a human issue, touching the very lives of the poor. Nor should we try to shift the blame from the Centre to the State, and *vice versa*. Coming, as I do, from Rajasthan, naturally, I would devote myself a little more to the conditions prevailing in my State. Rajasthan is facing one

of the worst drought for the fifth year in succession. This year, the rainfall has been the lowest during the last one hundred years. There has been a scanty rainfall, that is, -64% (minus 64%). All the 32 districts of Rajasthan have been affected by drought, and 40,689 villages of the State have been the worst-hit, causing untold misery to the population of 4.5 crores in these villages. As many as 4.62 crore cattle have been affected by drought. They have had neither water nor fodder, for days together. It has been reported that cattle could not get drinking water for two to three days at a stretch. No wonder, a large number of people, alongwith their cattle, are migrating to the neighbouring States in search of water and fodder. Seventy-five per cent of the population in the State depends on agriculture, a larger portion of which lives on cattle, sheep and goat- breeding. Animal husbandry is the mainstay for majority of the rural population of the State. With the severest drought this year, there is a shortage of fodder even in the neighbouring States. As a result, the prices of fodder have risen from Rs.300/- per quintal to Rs.400/- per quintal. The poor people cannot afford this. As a result, hundreds of cattle are dying, and carcasses are found strewn along the roads and the streets. There has been an acute shortage of drinking water even for the human beings, and the situation is deteriorating day-by-day.

Against the target of 129 lakh hectares for the kharif crop, only 60.89 lakh hectares could be sown. Out of this, 48.6 lakh hectares of crop, worth Rs.4417 crores, have been damaged. Owing to the shortage of water and damage to crops, the farmers and the farm labour have been put to severe problems of food and livelihood. In addition to this, the scarcity of fodder and water for the cattle has made the life of the villagers miserable. While I would not like to politicise the issue and divide the burden of blame, I would be failing in my duty to the people whom I represent, if I don't point out the inadequacy of relief measures provided by the Centre to the State. The State Government, despite its precarious financial situation, started taking all relief measures, right from August this year. Recurring drought and the absence of adequate assistance from the Central Government have broken the backbone of the State's finances. During the last three years, the State Government spent Rs.294 crores from its own resources, and took Rs.144 crores, from NABARD. During the year 2000-2001, the State Government submitted a memorandum of assistance for Rs. 1144 crores under the National Calamity Contingency Fund (NCCF), but the Government of India gave only Rs. 102.93 crores. During 2001-2002, against the demand of Rs.2367 crores, only Rs.163.97 crores were allocated. Again, in this year,

as against the demand of Rs.7519 crores, no funds under NCCF have been allocated so far. While the Centre should be fair and just to all the States, equally, it should also seem to be fair to all. In this context, it is noteworthy that as against the demand of 46 lakh tonnes of wheat, only 2 lakh tonnes were allocated to Rajasthan. While comparatively much more affluent States than Rajasthan have been allotted much more wheat. A Central study team had been sent to Rajasthan in the first week of September, and yet little action has so far been taken for rendering assistance under the NCCF. In this context, I cannot help recalling the speedy action taken during the severe droughts of 1987-88 under the Prime Ministership of late Shri Rajiv Gandhi. The then Government took a decision within 30 days of the visit of the Central team to render adequate help to the State. I gather that there have been numerous meetings of the Task Force, in the meantime, but no concrete steps have been taken to render any assistance under the NCCF. In the absence of a positive decision for such an assistance, relief operations by the State Governments have come to a naught.

The attitude of the Central Government in dealing with the calamity of this magnitude has been rather irresponsive, discriminatory and, I may say so, inhuman. I should not say that political considerations have come to play in delaying decisions on such crucial issues. I cannot help saying that the Central Government has failed in its constitutional obligation of helping the constituent States like Rajasthan in times of calamity under the National Calamity Contingency Fund Scheme. The Union Government is duty bound to provide assistance to the States in the case of calamities of rare severity. So much so, in the last three years, the Centre has not constituted the National Centre for Calamity Management, as provided under the NCCF Scheme.

Before I conclude, I wish to clarify a couple of points that were raised by my colleague, from the other side, about not lifting of the stocks by the Government of Rajasthan. Here, I would like to clarify, as has been done by my colleague, Mr. Meena, the stocks which he was referring to were the APL stocks that the price offered by the Government was practically the same, as what was being sold in the open market. And, since the quality in the open market was much better, this APL stocks were not lifted. And, he also mentioned about the famine deaths, which again was clarified by my hon. colleague, Dr. Abrar Ahmed, that he had personally gone to Baran where he has the video-tape of the parents of those children who died saying that they did not die because of famine.

I welcome the assurance given by hon'ble Prime Minister, as suggested by hon'ble Leader of the Opposition, for a permanent solution to the problem of recurrent droughts such as linking the major rivers in the country, comprehensive review of the Drought-Prone Area Programmes and the Desert Development Programme.

Once again, I wish to draw the attention of the Union Government to the gravity of drought situation in Rajasthan and urge upon the Centre to provide immediate assistance, as sought for by the State Government. Failing this, the situation is likely to deteriorate further.

With these words, I thank the Chair once again for giving me this opportunity.

SHRI THANGA TAMIL SELVAN (Tamil Nadu): Sir, before I begin my maiden speech, I take this opportunity to express my profound gratitude to my revered leader, the hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi Amma, who has sent me to this august House. I am beholder to Amma for sending commoner like me to this House of Elders.

As I rise to speak on the drought situation in the country, I am reminded of a couplet from Thirukkural, a grand treatise on universal truth.

The translation of couplet goes thus:

> "Though oceanic waters surround it,
> the world will be deluged by hunger's
> hardships, if the billowing clouds
> betray us."

Though this great world is surrounded by oceanic waters, if monsoon fails, all the creatures on the earth will be tormented by hunger and misery.

Drought has become a routine phenomenon affecting several States every year. My State of Tamil Nadu has been very badly affected by drought. In fact, monsoons have failed repeatedly in Tamil Nadu since the year 2000. Cauvery water also did not reach the Cauvery delta farmers, compounding the problem. Besides affecting the crops, the drought has led to severe drinking water shortage as well. The Tamil Nadu Government, under the able leadership of the hon. Chief Minister, Dr. Puratchi Thalaivi,

has taken several commendable steps to help the people to tide over the drought situation.

Due to the failure of south-west monsoon during the current year, 19 districts have been affected by drought in Tamil Nadu. The Central team visited the drought-affected areas of Tamil Nadu and on 23rd September, 2002 submitted a report to the Government of India. The Government of Tamil Nadu have asked for financial relief to the tune of Rs.1,434 crores and 5.5 lakh metric tonnes of foodgrains for tackling drought conditions. Upto 23rd September, 2002, the Government of Tamil Nadu, under the able leadership of Dr. Puratchi Thalaivi, provided Rs.67.90 crores from the Calamity Relief Fund to those districts which are affected by drought. Our beloved Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi, also conducted a meeting at Thanjavur on 24th June, 2002 and announced a special relief package of Rs.164.18 crores to the drought-affected areas of Cauvery Delta of Thanjavur, Thiruvarur and Nagapattinam Districts.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA) in the Chair]

Our hon. Chief Minister also announced a Deepavali gift for Cauvery Delta area to 10 lakh farmers and agricultural labourers at a total cost of Rs.21 crores. It has now been reported in the press that the Central Government has granted to Tamil Nadu Rs.228 crores towards drought relief. But, so far no official intimation has been received by the Government of Tamil Nadu. The allotment of drought relief to Tamil Nadu is very meagre and it is not enough to tide-over the prevailing drought situation in the State. Though the Central team is said to have recommended Rs.500 crores for drought relief, the Centre has released only Rs.228 crores, less than half of it. The Government of India should come forward to allot a huge amount as drought relief to Tamil Nadu.

Due to the non-release of Cauvery waters by the Karnataka Government to Tamil Nadu as per the interim order of the Cauvery Water Tribunal, the Kuruvai crops in Tamil Nadu, Cauvery Delta in particular, wilted causing a huge loss. After the intervention of the Supreme Court, the Karnataka Government began releasing water in Cauvery and yet the farmers, who have raised Samba Crops, are yet to get relief from the present situation. The Tamil Nadu Government has prepared a detailed statement and sent it to the Government of India on 5th August, 2002 requesting it to release Rs.720 crores from the National Calamity Contingency Fund and 2 lakh tonnes of foodgrains for drought relief work.

A delegation of AIADMK MPs too called on the hon. Prime Minister on 20^{th} August, 2002 and presented him a request of the State Government.

Non-release of Cauvery water has also affected the power generation in the State. The generation of hydel power at Mettur has come down to 2,000 million units as against 4,500 million units resulting in a loss of Rs.750 crores to the Tamil Nadu Electricity Board. 95 per cent of the tanks in our State have gone dry and the cultivation activities were only 50 per cent of the total cultivable area of Tamil Nadu. Eleven lakh coconut trees have wilted and another 28 lakh coconut trees are badly affected resulting in a loss of more than Rs.180 crores. The total production loss of crops due to drought in Tamil Nadu is estimated at Rs.3,200 crores. Subsequently the drought-afected districts were badly affected due to the scarcity of drinking water.

Listing out the requirements under various heads, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi, conveyed to the Central team that Tamil Nadu required a minimum cash assistance of Rs.1,434 crores and food-grains to the tune of 5.5 lakh tonnes. Even though the Tamil Nadu Government is reeling under severe financial crisis, the Government undertook the following relief works for the drought-affected districts of Tamil Nadu to help the people.

The Sampoorna Grameen Rozgar Yojana, Rural Prime Minister's Sadak Yojana, De-silting of B,C & D canals, forming of Farm Ponds, Eradication of IPOMEA (Neyveli Kattamanakku) weed, additional connection for pump-sets and construction of bridges were undertaken at a cost of Rs.164.18 crores.

I am happy to learn about the statement of the hon. Prime Minister that the linking of rivers shall be expedited. This announcement has raised the hopes of lower riparian States like Tamil Nadu, whose rights have been affected. I welcome that thoughtful statement. It may not be out of place to mention here that the celebrated poet Subramania Bharathi dreamt of a day when the rivers would be linked leading the nation to prosperity. In 1984, my leader Dr. Puratchi Thalaivi, as an hon. Member of this House, demanded nationalisation of rivers in the country. Nationalisation is very vital for the linking of rivers. That is why, my leader has been demanding nationalisation of rivers. I hope, the hon. Minister will make his stand clear on the nationalisation of rivers while replying to this discussion. I am very

particular about this because Tamil Nadu is the worst sufferer as the lower riparian State. On the one hand, we are deprived of our due share of Cauvery Water, and on the other, we are not allowed to store enough water in Periyar Dam. We have spent several crores on strengthening the dam as desired but still Tamil Nadu is not allowed to raise the storage height of Periyar Dam from 136 feet to 152 feet. Six districts of Tamil Nadu, namely, Theni, Dindigul, Madurai, Virudhunagar, Sivagangai and Ramanathapuram are completely dependent on this storage water for irrigation as well as drinking. But, the Kerala Government refuses to allow storage beyond 136 feet without any valid reason. Water is shared even among warring nations and battling principalities. But in a federal set-up, the due share of water is refused to a sister State. It is a matter of grave concern that even available plenty is not shared among the neighbouring States. This trend is against the federal spirit of our Constitution. So, I request the hon. Minister to prevail upon the upper riparian States and get the due share of water to Tamil Nadu. To save the entire country from natural calamities, the way is either to nationalise the river waters or to interlink the rivers of our country. The estimated cost of Ganga-Cauvery linking is now Rs.70,000 crores and it will take, at least, 10 years to complete this work. In order to complete the work at the earliest and to save our country from the extreme damages caused by flood and drought, the Central Government should come forward to borrow loan from the World Bank in order to complete the work at the earliest and to save our country from the exatreme damage of food and drought.

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इस सदन के 196 अधिवेशनों में बहुत कम ऐसे अधिवेशन रहे होंगे जिनमें बाढ़ या सूखे पर चर्चा न हुई हो। लेकिन विडम्बना यह है कि स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। पचास वर्ष से अधिक समय हो गया है, स्वतंत्रता के बाद से अभी तक हमारे देश में जल प्रबन्धन की व्यवस्था नहीं हो पायी है। सरकारें आयीं और गयीं, घोषणाएं बहुत हुईं, नदियों को आपस में मिलाने की बहुत पहले से घोषणाएं हुईं, आज भी नये सिरे से हो रही हैं लेकिन हमारे देश की परिस्थितियों में जो जल प्रबंधन होना चाहिए, उस जल प्रबंधन पर कभी नहीं सोचा गया, उस पर कभी विचार नहीं हुआ और वैसी व्यवस्थाएं नहीं की गयीं । हम बड़े-बड़े बांधों की ओर तो देखते रहे और उनको बनाते रहे लेकिन जो अपने देश की परिस्थितियां हैं, हमारे देश की परिस्थितियां मानसून के चलते बड़ी विचित्र हैं । हमारे देश को मौसम विभाग ने 35 क्षेत्रों के रूप में बांटा है, अगर हम हर साल के आंकड़ों को देखें तो हम पाएंगे कि इन 35 क्षेत्रों में हर वर्ष कुछ क्षेत्रों में सूखा होगा और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आएगी । यह सिलसिला लगातार चल रहा है और यह बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे देश की परिस्थितियों में सूखे और बाढ़ को अलग करके नहीं सोचा जा सकता । ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं । इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए । अगर हम अपने मौसम विभाग के जरिए से दिये गये

आंकड़ों की ओर देखें तो हम यही पाएंगे कि हर वर्ष जो 35 क्षेत्र हमारे मौसम विभाग ने बांटे हैं, इनमें से कुछ क्षेत्र सूखे की चपेट में रहते हैं और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उसी वर्ष बाढ़ आती है । श्रीमन्, मैं यहां पर कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं । अंडेमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सामान्य से कम वर्ष 1992, 1997 और 2000 में हुई । मौसम विभाग ने एक अजीब स्थिति हमारे देश में यह कर दी है कि विचलन की स्थिति वह माइनस उन्नीस परसेंट सामान्य से कम मानता है और प्लस उन्नीस अधिक मानता है जबकि बात ऐसी नहीं है । क्योंकि सिंचाई की अन्य व्यवस्थाएं हमारे यहां खेती के लिए नहीं है, इसलिए वर्षा में 10 प्रतिशत की कमी भी सामान्य से कम मानी जानी चाहिए । यह नहीं माना जाना चाहिए कि अगर सामान्य से 19 प्रतिशत कम बारिश हो तो उसे कम बारिश माना जाए । 10 प्रतिशत अगर कम वर्षा किसी क्षेत्र में हो तो वह सामान्य से कम वर्षा मानी जानी चाहिए क्योंकि हमारे यहां की कृषि ऐसी नहीं है । अरुणाचल प्रदेश में 1992, 1994 और 2001 में, असम और मेघालय में 1992 और 1994 में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 1994 में, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम में 1992 और 1994 में, उड़ीसा में 1996 और 2000 में, झारखंड में 1992 और 1996 में, बिहार में 1992 और 1994 में, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2001 में, उत्तरांचल में 1992 और 1996 में, इसी प्रकार से अगर आप सूखे की स्थिति को सूबों में देखेंगे तो उन्हीं वर्षों में बाढ़ की स्थिति दूसरे सूबों में मौजूद है । उन्हीं वर्षों में कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ा है, जबकि अन्य प्रदेशों में बाढ़ आयी हैं । हमारे यहां जो स्थितियां हैं, जो मौसम विभाग के जरिए से हमें प्राप्त हैं और जो हम अनुभव से महसूस करते हैं, वह यह है कि हमारे देश की मानसून की व्यवस्था ऐसी है कि हमें जल प्रबंधन को देखना होगा और हमें जल प्रबंधन की व्यवस्था करनी होगी । ऐसा नहीं है कि यह कोई नयी बात है। हमारे देश में पूर्वजों ने भी इस व्यवस्था को किया था लेकिन स्थितियां क्या हो गयीं कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में जहां उन स्थितियों को हमें लाना चाहिए था, अपने यहां की परिस्थितियों को देखकर, वह न करते हुए हमने बड़े बड़े देशों की नकल पर बड़े-बड़े बांध बनाने की योजनाएं बनाईं । हमारे यहां तालाब खत्म हो गये । हमारे देश में 6 लाख तालाब थे । आज तालाब कुछ हजार ही शेष रह गये हैं । यह निश्चित बात है कि अगर हम तालाबों की ओर नहीं जाएंगे, अगर हम जल प्रबंधन की ओर नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से न तो हम सूखे की समस्या से निपट पाएंगे और न ही बाढ़ की समस्या से निपट पाएंगे । इसलिए मेरा सबसे पहला निवेदन तो यह है कि इस सरकार को इस बात के लिए सोचना चाहिए कि इस संबंध में राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए और राष्ट्रीय नीति तब बनेगी जब जल सम्पदा को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित किया जाएगा । जो पूरे देश में जल सम्पदा है, उसको राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित किया जाए और केन्द्रीय सरकार उसका ऐसा नियमन करे कि हर क्षेत्र को सूखे से भी बचाया जा सके और उन क्षेत्रों को जहां बाढ़ आती है, उनको बाढ़ से बचाया जा सके, तब हमारे देश की समस्या हल होगी । लेकिन इस वर्ष जो सूखा हमारे देश में पड़ा, जो कभी-कभी पड़ा करता है पूरे देश में, वह स्थिति इस वर्ष हमारे यहां आई । सरकार ने खुद माना कि जुलाई महीने के अंत तक 73 प्रतिशत कमी वर्षा की हुई पूरे देश में । सारी खरीफ की फसलें चौपट हो गईं । उत्तर प्रदेश में धान पैदा नहीं हो सका, किसान उसको बचा नहीं पाया । किसी ढंग से उसने गन्ना बचाया, अपनी पूरी लागत लगाने के बाद, अपने पेट को काटने के बाद उसने किसी तरीके से गन्ने को बचाया लेकिन आज गन्ना सूख रहा है । सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है । क्या यह आपात स्थिति नहीं है ? क्या इसका दायित्व केवल राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा ? अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए केन्द्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं के विषय को राज्य

सरकारों के ऊपर थोप देती है । कोढ़ में खाज की स्थिति यह है कि इसके आधार पर हम राजनीति भी कर रहे हैं । कुछ सूबे ऐसे हैं, कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनमें भेदभाव करते हुए उनको सूखाग्रस्त घोषित किया गया और कुछ को नहीं किया गया । उत्तर प्रदेश में ऐसा ही हुआ। उसी प्रकार केन्द्र सरकार भी बची हुई नहीं है । लेकिन यहां पर यह प्रश्न नहीं है, यह आपत्ति नहीं है कि आंध्र प्रदेश को क्यों ज्यादा दिया गया ? यह आपत्ति नहीं है । कोई इस पर आपत्ति नहीं करेगा, वाकयी में आंध्र प्रदेश और राजस्थान में बहुत ही विषम परिस्थितियां पैदा हुईं लेकिन इस पर आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो इस बात पर है कि जिन परिस्थितियों में आंध्र प्रदेश को केन्द्र सरकार ने मदद दी, उन्हीं परिस्थितियों में अगर दूसरे सूबों में भी वह मदद करती तो कोई आपत्ति का सवाल नहीं था । 2001-2002 के दौरान पूरे देश में आपात स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने जो राज्य सरकारों को सहायता में जो बढ़ोत्तरी की है, वह 2.6 प्रतिशत की है और आंध्र प्रदेश के लिए जो बढ़ोत्तरी की है, वह 31 प्रतिशत है । हम यह नहीं कह रहे कि उनको यह बढ़ोत्तरी क्यों दी गई । उनको दी जानी चाहिए, और आगे भी दी जानी चाहिए लेकिन हमारा कहना यह है कि अगर ऐसी ही परिस्थितियां दूसरे सूबों में हैं, चाहे वह राजस्थान में हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हैं, चाहे बिहार में हैं, उन परिस्थितियों में उतनी ही सहायता केन्द्र को उस राज्य को भी देनी चाहिए, असल प्रश्न इस बात का है । श्रीमन्, मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इस बात को सोचे और इस विषय में राजनीति से ऊपर उठकर चले । इसके पूरे कारण हैं कि किस कारण से किस प्रदेश को कितनी मदद दी जा रही है लेकिन हम उन बातों में नहीं जाना चाहते । हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि जो परिस्थितियां आंध्र प्रदेश में मौजूद हैं, उन्हीं परिस्थितियों की मौजूदगी अगर दूसरे प्रदेशों में भी है, तो उनको भी उतनी ही प्रतिशत मदद में बढ़ोत्तरी मिलनी चाहिए ।

महोदय, 21.5 लाख टन चावल हाल में ही आंध्र प्रदेश को दिया गया है सितम्बर के महीने से अब तक । क्या किसी और प्रदेश को दिया गया है, वह भी बिना मूल्य के ? यह प्रश्न नहीं है, हमें उस पर आपत्ति नहीं है कि आंध्र प्रदेश को और मदद मिले, लेकिन हमारा कहना यह है कि अगर वही परिस्थितियां राजस्थान में हैं और अगर वही परिस्थितियां दूसरे सूबों में हैं तो वह सहायता उतनी ही मात्रा में उनको भी मिलनी चाहिए ।

लेकिन हमें यह ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार जो यह कहती है कि 11वें वित्त आयोग ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए केवल 11 हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, यह कहकर केन्द्रीय सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है । यह कहना कि आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारें हैं, केन्द्रीय सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है । उसे यह छोड़ना चाहिए ।

महोदय, जल प्रबंधन केन्द्रीय सरकार का विषय होना चाहिए, जल सम्पदा राष्ट्रीय सम्पदा घोषित होनी चाहिए और केन्द्र सरकार को उसका नियमन करना चाहिए । ऐसा प्रबंधन करके जिससे सूखे और बाढ़ की चपेट से हम देश को बचा सकें, सरकार को काम करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद ।

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, आज सचमुच भारत की महान जनता और किसान बड़े भारी संकट में पड़े हुए हैं । भारत भयानक सूखे से ग्रसित है । इसमें हम कहीं राजनीति की

बात नहीं कह सकते । भारत की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है, कृषि, वह आज पूरी की पूरी चरमराती जा रही है । भारत अन्य देशों से इसलिए भिन्न है कि भारत की इकनोमी कृषि पर टिकी है। संपूर्ण भारत की आबादी लगभग एक अरब पांच करोड़ तक पहुंच गई है। इतनी बड़ी जनसंख्या, उसका विकास और उसकी रोजी-रोटी के प्रबन्ध का अगर एक ही तरीका है, एक ही क्षेत्र है तो किसान और हमारी खेती है। हम देश का राज-काज चलाने वाले लोग हैं। इस ओर सरकार का और हमारा ध्यान नहीं रहा है। कोई प्लानिंग नहीं है और कोई योजना नहीं है। महोदय, हर साल बाढ़ और सुखाड़ के तमाचे से किसान तबाह है। प्रधानमंत्री जी डंका बजा-बजाकर बोलते हैं कि हम 8 प्रतिशत विकास की दर प्राप्त करेंगे। यह बिल्कुल खोखला साबित हो रहा है। आईटी की बात हम करते हैं, इन्फॉर्मेशन टैक्नॉलोजी की बात करते हैं। जब कुदरत ने, नेचर ने, प्रकृति ने हमें धोखा दिया है तो जो सारी आईटी व्यवस्था और इन्फॉर्मेशन टैक्नॉलोजी है, यह बिल्कुल विफल साबित हुई है। कल भाई-भाई में जो युद्ध होने वाला है, उसका एक लक्षण जो कर्नाटक और तमिलनाडु के किसान हैं, भारत की जनता को देखने को मिल रहा है। हमारी जमीन और धरती मां की छाती फट रही है, मुरझाती हुई फसल को देखकर। किसान जिस तरह से अपने बेटा और बेटी को समझते हैं, उसी तरह से भारत का किसान खेती और पौधों को समझता है। महोदय, हालत बद से बदतर है। विगत कई वर्षों से भारत का जो जल संसाधन विभाग है, इस पर लोएस्ट इंवेस्टमेंट है, कम से कम खर्च के कई कई तरह के तकनीकी कारण बताकर, हमें ध्यान देना चाहिए, बिना पानी के सारी बातें विफल हैं। मैं जिस राज्य से आता हूं, शुरू के दिनों में जब यह सीड प्लांटेशन का नक्षत्र शुरू होता है, भीषण सुखाड़ है, उस समय बिहार में बारिश नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय नदियां नेपाल से होकर बिहार में आती हैं। उत्तर बिहार में वेस्ट और फर्टाइल लैंड हैं, वहां पांच-पांच फीट तक पानी जमा हो जाता है, वहां हमारा डेनसिटी आफ पॉपुलेशन जहां थिक है। गंडक, अधवारा, बूढी, कमला बलाम, महोदय आप अवगत हैं, आप उत्तर बिहार की जनता को जानते हैं, हर साल अंतर्राष्ट्रीय नदियों के तमाचे से हम बाढ़ का मुकाबला करते हैं। हम से हिसाब लिया जाता है कि बिहार में सड़क अच्छी नहीं है। पांच फीट पानी सड़कों से गुजरता है और पूरे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेल लाइन को उखाड़ता है और वाटर लॉगिंग हो जाती है। हमारी भारत सरकार ने कितनी बड़ी भूल की है, हमारी गंगा मां का पानी बंगलादेश को हमने दान कर दिया। आज हमारी नदियां सूखी हैं। आप आसानी से गंगा में पैदल निकल सकते हैं। गंगा का बेड़ भरता जा रहा है। भारत सरकार बोलती है कि हल्दिया से हम कानपुर तक नेविगेशन का काम करेंगे। लेकिन आप ड्रेन आउट नहीं करिएगा । हमारे बिहार का लाखों मछुवारे हैं। उल्टा समुद्र से मछलियां चढ़ती थी, ब्रिडिंग होती थी, वह भी समाप्त हो गया है। मेरा यह कहना है कि अगर बिहार की फसल है, बिहार में खेती है तो अन्य राज्यों में जहां हमारे भाई बन्धु हैं, जहां अनाज नहीं है वहां हम अनाज भेज सकते हैं। हम तमिलनाडु से मंगा सकते हैं, आन्ध्र से मंगा सकते हैं। आन्ध्र से हम अंडा लेते हैं, मछली लेते हैं और सारा सामान लेते हैं। हम भारत के अंदर अपनी व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कृषि विभाग की क्या योजना है और उसकी सोच क्या है ? यह कोई एक दिन की बात नहीं है । वर्षा का जो औसत है वह धीरे-धीरे बदल रहा है । हमारे मुल्क में बेटाइम वर्षा हो रही है । विगत दिनों में जब सूखाड़ पड़ता था तो डा. राम मनोहर लोहिया जी फूड फार वर्क, काम के बदले अनाज की योजना के बारे में कहा करते थे । उस समय लोहिया जी कहा करते थे कि जब सूखा हो तो हमें जो सौ टन ग्रेन है, अनाज है, उस पर ध्यान देना चाहिए । जो अनाज है, मडुआ है, जिसे कर्नाटक में रागी बोलते हैं, हमारे

यहां मदुआ, सागी, कोहो बोलते हैं, बाजरा और यह सारा जो दलित अनाज है, जो बैक्वर्ड अनाज है उस दलित, बैकवर्ड अनाज की सीड को अपर कास्ट अनाज का जो व्हीट है, राइस है, ने उसकी सीड को समाप्त कर दिया है । इस पर कृषि विभाग की जो सोच है उसकी नादानी की वजह से ही हमारी यह सीड आज खत्म हो रही है । ज्यादा बारिश हो जाए तब भी वह फसल होती थी, कम बारिश हो जाए तो लाठी खोंस-खोंसकर हम लोग प्लांटेशन करते थे । कम पानी रहता था तब भी हमारे पुरखे करते थे । बहुत कम समय में खेती होती थी । अब हाई ब्रीड की बात है । हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, आप रिसर्च कर रहे हैं, कीजिए लेकिन हम ऐसी सीड मंगा रहे हैं जो निर्वन्श साबित हो रही है । जिसका आगे कोई वंश नहीं होने वाला है । फिर हमें बाहर से लेना पड़ेगा । हमें निर्वन्श नहीं चाहिए, हमें कमाऊ चाहिए । महोदय, हमारे देश का जो वाटर मैनेजमेंट है, इसके लिए इस देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी लगातार गारलैण्ड स्कीम के बारे में बोलते थे । एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ो, माला की तरह बनाओ । इस बात को हमने अखबारों में पढ़ा । कल जब वहां लोकसभा में बहस हो रही थी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है । हम नदियों को जोड़ देते हैं । देहात में लोग कहते हैं कि "न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी" । कैसा सब्जबाग दिखाया जा रहा है । इस देश के किसानों और मजदूरों के साथ किस तरह से धोखा हो रहा है । आज चारों तरफ खून-खराबा होने वाला है । आपके पास अंडर ग्राउण्ड वाटर कहां है ? कुदरत ने हमें बिहार में सौ फीट तक अंडर ग्राउण्ड वाटर दिया है । पेट्रोल भी हमारे बिहार में है । पानी है लेकिन एक बिहार से काम नहीं चल सकता है। राजस्थान में पीने का पानी लाने के लिए हमारी मां-बेटियां कई किलोमीटर तक चलती हैं । बिजली से भी पानी निकालते हैं लेकिन अंडर ग्राडण्ड वाटर का जो स्रोत है वह नीचे सूखता जा रहा है । कितना भारी संकट है, कितना बड़ा खतरा है । अगर समय रहते हमने ध्यान नहीं दिया तो इस देश में अशांति होने वाली है । लोग बोलते हैं कि हम सब लोगों को मिलकर इंतजाम करना चाहिए । क्या इंतजाम करेंगे ? जब ऊपर से बारिश नहीं होगी तो नदी में पानी कहां से आएगा ? नदी में पानी नहीं आएगा तो कैनाल में कहां से आएगा ? हमें इसके बारे में सोचना चाहिए । हम लोग सुनते थे, जानते हैं और हम लोगों ने सुना है कि सैकड़ों-हजारों वर्ष पहले भी बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों के समय में भीषण सूखा पड़ता था, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी ऐसा कहा गया है कि जब शासक या राजा पापी होता था तो बारिश भी कुदरत का साथ नहीं देती थी । यह हमारा धर्म है । लेकिन इस देश में अधर्म हो रहा है । देहात में जब बारिश नहीं होती तो हमारी मां-बहिन घयली में गोबर सानकर, अबेन पकड़कर, गांव में जो बूढ़ा आदमी सोया रहता है उसके सामने लाकर पटक देती है और गाना गाती है कि हाली-हाली बरस गोसइया परमेश्वरा, पानी बिना पड़ल बया काल हो राम । तब बारिश भी हो जाती थी लेकिन आज जो हमारी संस्कृति भी है और विरासत भी है, उसमें बारिश नहीं हो रही है । यहां दिल्ली में, जहां हम लोग बैठे हैं, यहां भी पानी के लिए चारों तरफ हा-हा कार मचा है । शहर में रहने वाले लोगों की हालत भी बद से बदतर होने वाली है । इन कारणों पर हमें गहराई से विचार करना पड़ेगा । क्यों मानूसन हमको धोखा दे रहा है? क्यों हमारे पास पानी नहीं है? कारण क्या है? इन कारणों पर हमने ध्यान नहीं दिया और आल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं की है। पानी की योजना नहीं बनायी है। यह कोई जरूरी नहीं है कि केवल इस साल सूखा पड़ा है, हो सकता है आने वाले समय में भी ड्राउट का मुकाबला करना पड़े। जो हालत है उसके लिए कृषि विभाग के पास कोई सोच है कि नहीं? प्रधान मंत्री जी के पास, उनके विभाग के पास है कि नहीं?

4.00 P.M.

राज्यों को मदद करने में, राहत देने में भी भेदभाव किया जा रहा है महोदय। पूरे मध्य बिहार में प्लांटेशन नहीं हुआ। यह तो उत्तरी बिहार में फ्लड आने से हमारी कुछ खेती हो गयी। अभी कुदरत ने हमें अपार बारिश दी। हमारे यहां बिहार में बम्पर खेती है। लेकिन ड्राउट के राज्यों को ज्यादा मदद पहुंचाइए। सीआरएफ का जो फंड है, ठीक कहा हमारे कांग्रेस के एक एम पी साहब ने कि आप जो सहायता कर रहे हैं यह तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इसमें भी बीपीएल, अगर गरीबों में बांटने जाइए तो किसान लाठी लेकर खड़ा हो जाता है। हमारी खेती मारी गयी है। इसलिए महोदय, हमको इस पर काफी ध्यान देना पड़ेगा।

हमारी जो कृषि है, जो हमारी इकनामी है इसके लिए एक सशक्त नेतृत्व, कुशल नेतृत्व चाहिए जिसने गांवों को झेला हो, जिनके पैरों में बिवाई फटी हो, ऐसा नेतृत्व जो गांव विरोधी नहीं हो, किसान विरोधी नहीं हो, मजदूर विरोधी नहीं हो। ऐसा नेतृत्व जब तक भारत को नहीं मिलेगा तब तक यह जो संकट है, यह हमारा संकट मिटने वाला नहीं है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि सूखे का मुकाबला करने के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था है और ऐसे अनाजों, ऐसे सीड्स का अभी से इंतजाम करना चाहिए जो कम बारिश होने पर भी उगें। हम अमेरिका का सीड यहां नहीं लगा सकते हैं। हमारा देश सिंगापुर, अमेरिका या कनाडा नहीं है। हमारी अलग अलग व्यवस्था है। हर रीजन में अलग अलग खेती है। अलग सीड्स हैं। ऐसी चीजों पर थ्रस्ट करना पड़ेगा अन्यथा पशु कमजोर हो रहे हैं, लोगों को चारा नहीं मिलेगा। खेती नहीं होगी। हालत बद से बदतर है। इसलिए इस पर भारत सरकार का क्लियर कट ध्यान होना चाहिए कि ये क्या करना चाहते हैं, सुखाड़ से आगे निपटने के लिए, कब से और कौन से कदम उठा रहे हैं। किसानों को कान्फीडेंस में लेना चाहिए।

आपको बहुत, बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका जिक्र प्रायः हम हर वर्ष करते हैं। वैसे ही सूखे की समस्या है जो सदैव बनी रहने वाली, दीर्घकालीन समस्या है। हमेशा इस बात पर जोर दिया जाता है कि हम इसे गंभीरता से लें। इसके बुनियादी हल को खोजें, बुनियादी कारणों को खोजें। केवल हम तात्कालिक कदम न उठाएं बल्कि दीर्घकालिक कदम उठाएं और कारणों को गंभीरता से खोजकर हम गंभीरता से कदम उठाएं। लेकिन हर वर्ष यह होता है कि कभी हम बाढ़ की समस्या का जिक्र करते हैं और कभी हम सूखे की समस्या का जिक्र करते हैं-और जिक्र, जिक्र रह जाता है। जो समुचित पहल होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जहां सरकार इसे गंभीरता से ले वहीं वैज्ञानिक भी मिल-जुल कर इस गंभीर समस्या के बारे में विचार विमर्श करें कि सूखे की समस्या के निदान के लिए क्या समुचित उपाय उठाए जाने आवश्यक हैं। हमेशा यह बात आती है कि सूखा संहिता बने। कोई सजेशन देता है कि मौसम संहिता बननी चाहिए। हमारे यहां अंतरिक्ष विभाग, स्पेस विभाग में ऐसी व्यवस्था है कि कहां कितनी वर्षा होने वाली है उसका आंकलन यदि हम पहले से कर लें और पहले से ही हम कुछ कदम उठा लें तो मैं सोचता हूं कि इस समस्या से आंशिक रूप से हम कुछ छुटकारा पा सकते हैं। पूर्ण मैं नहीं कह रहा हूं। मिसाल के तौर पर यदि किसी जिले में सूखा पड़ने वाला है, क्योंकि मैं किसान परिवार से संबंधित हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, वो वहां यह बता दें, जैसे हमारे यहां सरकार ने बताया कि रायसेन, सिहोर और

होशंगाबाद जो जिले हैं, चूंकि मध्य प्रदेश में सब से ज्यादा सोयाबीन की पैदावार होती है, सूखा पड़ेगा इसलिए आप साथ में बाजरा बोइए वरना आपकी सोयाबीन की फसल खराब हो जाएगी । इसलिए आल्टरनेट क्रॉप क्या होनी चाहिए, क्या बोया जाना चाहिए, इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए । लेकिन यह दायित्व, मैं नहीं कह रहा हूं कि यह राज्य सरकारों से हट कर केन्द्र सरकार का है, बल्कि इसमें दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है । इसलिए जब मैं यह कहता हूं और सारे हमारे वक्ता इस बात से सहमत होते हैं कि यह एक ऐसी समस्या है कि जिसको हमें राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए और न ही जिस पर राजनीतिक रूप से बात करनी चाहिए, वहीं हम यह भी सोचते हैं कि इस समस्या से जब कोई ग्रस्त हो जाता है तो जो ग्रस्त लोग हैं उनको राहत देने के लिए हमें राजनीतिक चश्में से भी नहीं देखना चाहिए, चाहे वह कांग्रेस शासित राज्य हों, चाहे गैर कांग्रेस शासित राज्य हों ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरे देश में 307 जिलों में सूखा पड़ा है जिनमें जो खास राज्य हैं, उनमें आन्ध्र प्रदेश में 22, कर्नाटक में 24, झारखंड में 22, महाराष्ट्र में 33, उड़ीसा में 30, राजस्थान में 32, गुजरात में 13 और अन्य राज्य भी हैं । प्रश्न यह उठता है कि इन राज्यों द्वारा कितने करोड़ रुपये इस समस्या से निपटने के लिए मांगे गए । मान्यवर, मैं ज्यादा समय इस विषय पर नहीं लेना चाहता, लेकिन तीन-चार बातों की ओर जब मैं इंगित करूंगा तो उससे सारी बात स्पष्ट हो जाएगी कि इस समस्या से निपटने के लिए कितने पैसे मांगे गए थे और कितने दिए गए । 2,193.96 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ ने मांगे थे, जो कि उन्हें नहीं दिए गए और 10 लाख टन खाद्यान्न मांगा गया था, जो कि पूरा का पूरा नहीं दिया गया । मध्य प्रदेश, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, वहां 32 जिले सूखे की स्थिति से गुजर रहे हैं, वहां 668 करोड़ रुपये मांगे गए थे, जो कि नहीं दिए गए । खाद्यान्न दो लाख टन मांगा गया था, जो कि एक लाख टन दिया गया । अभी और जब सूखा पड़ा है तो पांच लाख टन और खाद्यान्न मांगा गया है । पंजाब, वहां 800 करोड़ रुपये मांगे गए थे, लेकिन पैसा कितना मिला, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा ? माननीय मंत्री जी से मैं यह भी जानना चाहूंगा कि राजस्थान, जहां भयंकर सूखा पड़ा है, वहां 4,996 करोड़ रुपये मांगे गए थे, जबकि 1,124.79 करोड़ रुपये वहां अभी तक दिए गए हैं । यह सारी स्थिति है । अब यह स्थिति इस बात की ओर इंगित करती है कि ...(व्यवधान)... वह सैकंड लैटर था । उसके बाद जो सैकंड लैटर गया तब 762.39 करोड़ रुपये की मांग हुई, जिसमें 38 लाख टन गेहूं और 2,223 करोड़ रुपये, जो कि बाकी मैटीरियल के लिए खर्च होंगे, ऐसा राजस्थान सरकार का कहना रहा है ।

मान्यवर, मैं इन आंकड़ों में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं मात्र यह दर्शाना चाहता हूं कि जब हम सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बात कर रहे हैं तो जितना जिन राज्यों ने पैसा मांगा है उतना उन राज्यों को दिया जाए, इस आधार पर कि असैसमेंट वहां का क्या है। इसके लिए सैन्टर की टीम वहां जाती है । वह अपनी रिपोर्ट लंबे समय तक नहीं दे पाती है। जब तक वह अपनी रिपोर्ट देती है तब तक उस स्थिति से लोग गुजर चुके होते हैं । अभी कुछ स्थानों पर यह बात आई कि वहां जो मौतें हुई वे इस वजह से हो गई कि वहां लोगों के पास खाने को नहीं था । कुछ वहां खाद्यान्न नहीं था । मैं मध्य प्रदेश का जिक्र करना चाहता हूं । मेरे पास कलैक्टर, शिवपुरी, जो मध्य प्रदेश में आता है, उसकी रिपोर्ट है। उसने, वहां जो तीन मौतें हुईं, रविता पुत्री मकले कुशवाहा, जनो पुत्र घसीटा और तीसरी मौत नत्थू पुत्र सीता कुशवाहा, उसके बारे में बताया है कि इन तीनों के पास जमीन है, तीनों के घर में खाद्यान्न पाया गया, लेकिन ये

बीमारी में थे । यह मैं कोई पैरवी नहीं कर रहा हूं, कोई बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन मौत तो मौत होती है । अगर वह बीमारी की वजह से भी हुई हो तो भी उसकी चिकित्सा का इंतजाम होना चाहिए था । लेकिन कुछ राजनीतिक दल हैं जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की इन मौतों को एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं । मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि अच्छा यह होता कि इन प्रदेशों में जब यह महसूस किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सूखा पड़ा है तो इन प्रदेशों की सरकारों ने जितना पैसा मांगा है, उतना पैसा उन्हें उपलब्ध कराया जाता, तब तो कोई बात बनती । तब तो कोई बात होती वरन् इन सब बातों को उठाने और कहने से कोई मकसद हल नहीं हुआ करता है ।

मान्यवर, मध्य प्रदेश सरकार ने सूखे से निपटने के लिए ग्रेन बैंक स्कीम के संबंध में प्रपोजल केन्द्रीय सरकार को दिया है जिस के अंतर्गत इस स्कीम को आदिवासी गांवों में प्रारंभ किया जाएगा । मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस स्कीम के लिए केन्द्र सरकार से जितने पैसे मांगे गए थे, वह बिल्कुल ही नहीं दिए गए हैं । उन्होंने इस स्कीम को उन के ट्रायबल सब-प्लान में डायवर्ट कर दिया जिस से कि इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।

मान्यवर, अब प्रश्न आता है कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सावधानी के तौर पर क्या प्रारंभिक कदम उठाए जाने चाहिए । इस के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में पहले से सूखे के संकेत मिलते हैं, उन स्थानों के लिए पहले से समुचित कदम उठाए जाने चाहिए । आज पूरे देश में स्थिति यह है कि रबी और खरीफ की फसल बहुत ज्यादा प्रभावित हो गयी है । मान्यवर, हमारे देश में इरिगेटेड लेंड.29 से 40 प्रतिशत के बीच में है, शेष अन-इरिगेटेड लेंड के बारे में व्यवस्था के लिए कदम उठाए जाने के संबंध में विचार किया जाना चाहिए ।

मान्यवर, हमारी कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस दिशा में प्रधान मंत्री जी को 5 अगस्त, 2002 को एक पत्र लिखा था जिस में उन्होंने कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स से विचार-विमर्श के बाद सजेशन दिया था कि एक इंटर-मिनिस्टीरियल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया जाना चाहिए, ड्राउट मैनेजमेंट के लिए एक आल पार्टी कमेटी बननी चाहिए, नेशनल कैलामिटी फंड में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए और सेंट्रल टीम के असेसमेंट में डिले नहीं होना चाहिए । माननीया कांग्रेस अध्यक्षा के उस पत्र को 4 सितंबर को प्रधान मंत्री जी एक्नोलेज तो कर दिया, लेकिन एक-दो बातों को छोड़कर बाकी बातों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया जो इस बात को दर्शाता है कि प्रधान मंत्री जी और उन की यह सरकार सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कितनी गंभीर है ।

मान्यवर, मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं । जहां तक जल-प्रबंध का सवाल है, इस संबंध में हम महसूस करते हैं कि पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले कुएं बावड़ियों व तालाबों को उपयोगी बनाने के संबंध में भी आवश्यक कदम उठाए जाने की जरूरत है । अभी हमारे देश में जो नदियों का जाल है, उस से मोटे अनुमान से 4 प्रतिशत भूमि ही सींची जाती है। इस दिशा में महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रचलित रिवर डिस्प्यूट्स का सही ढंग से समाधान किया जाए । तीसरी बात, गांवों में तालाब, पोखर और बावड़ियों के रख-रखाव की भी जरूरत है । साथ ही रिवर वाटर के प्रॉपर कलेक्शन के बारे में भी आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है । इस के अतिरिक्त पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए जंगलों की रक्षा की जानी चाहिए ताकि मौसम के अंतर्गत आने वाले विषयों के असंतुलन को दूर किया जा सके ।

मान्यवर, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं गुजरात का जिक्र करना चाहता हूं । वहां लगभग 13 जिलों में सूखा पड़ा, लेकिन काफी दिनों तक इन 13 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया । उस के पीछे कारण यह था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से पर्याप्त पैसा नहीं आया तो कहीं चुनाव में ऐसा न हो कि दूसरे दल के लोग यह बात उठा दें कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है व दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा क्यों नहीं आया ? इसलिए वहां की सरकार ने लंबे समय तक इन 13 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने धरना दिया, जब कांग्रेस पार्टी ने रिपोर्ट दिया, तब उस के बाद मजबूर होकर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से असिस्टेंस की मांग की । लेकिन मुझे दुख है कि उस के बावजूद भी गुजरात राज्य ने जितने पैसे की मांग की थी, जितने फूड ग्रेंस की मांग की थी, वह उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया । यह बहुत ही अफसोस की बात है । इसलिए मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि इस दिशा में कदम उठाए जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है ।

मान्यवर, चूंकि अन्य वक्ताओं को बोलना है, मैं मध्य प्रदेश की बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ । मध्य प्रदेश सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए 668.62 करोड़ रुपए की मांग की है और मैटेरियल कंपोनेंटस के लिए, रिलीफ वर्क के लिए 2.5 लाख टन की और फूड ग्रेन्स की मांग की है । इसके बाद उन्होंने ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम के तहत मांग की है, नेशनल कैलेमिटी फंड के तहत सेकेंड इंस्टालमेंट की मांग की है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं ।

मान्यवर, मैं नहीं जानता कि इस चर्चा का उत्तर एक मंत्री देंगे, दो मंत्री देंगे, जूनियर मंत्री देंगे या सीनियर मंत्री देंगे, लेकिन एक मंत्री दें या दो मंत्री दें या तीन मंत्री दें या जूनियर मंत्री दें या सीनियर मंत्री दें, उनसे मैं आपके माध्यम से विनम्रता-पूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इन राज्यों ने कितने पैसे की मांग की, कितने खाद्यान्न की मांग की और आपने उनको कितना पैसा और खाद्यान्न उपलब्ध कराया, इसका विवरण वे अपने उत्तर में जरूर दें और बड़ी कृपा होगी अगर आप बताएंगे कि जो बाकी रह गया है उसको कब तक उपलब्ध करा पाएंगे। इस जानकारी से पता लगेगा कि आप सूखे के प्रति कितने चिंतित भी हैं, कितने विचलित भी हैं, कितने गंभीर भी हैं, इसका आप समाधान भी चाहते हैं, सूखे से पीड़ित लोगों के प्रति आपके मन में सद्भावना भी है और दर्द भी है वरना यह लगेगा कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हुआ करते हैं और खाने के कुछ और हुआ करते हैं । बहुत बहुत धन्यवाद ।

PROF. M. SANKARALINGAM (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, this year's drought is counted amongst the four worst droughts of the century. This situation was caused mainly by the prolonged dry spell in July, 2002, when the rainfall deficiency was 49 per cent. Only on two occasions, in the past, did rainfall deficiency exceeded 45 per cent in the month of July. The Indian Meteorological Department has declared the year 2002 as the South West monsoon failure sufficiently in advance. Nearly 15 States were affected, including Tamil Nadu severely. Several Hon'ble Members of this House have given details of their States' position, in particular, and the havoc caused by the drought in general. The ultimate

affecting people are farmers, who are the backbone of our society; upon whom our economy is based. Drought can convert agricultural lands as parched wasteland and our farmers as starving population. Many of the areas which suffered from drought are now suffering from heavier rains and floods. In Tamil Nadu, Thanjavur and Trichy are considered the rice bowl of the State. In these districts, the first crop is Samba crop which failed due to monsoon failure. So, also other districts like Villuppuram, Nagapattinam, Thiruvarur, Cuddalore, Madurai, Ramanathapuram, Theni, Tirunelveli and Kanyakumari, are under the grip of severe drought. Usually, in Tamil Nadu the first crop season is, June to August. Normally, the crop area would be 16.5 lakh hectares under the Samba crop cultivation. Normally good yields are reported, but this year, till now, only 4.78 lakh hectares land paddy crop are raised. The estimated loss is Rs. 1796 crore. The estimated loss due to the failure of the crop at the flowering stage is Rs.976 crores. Now, the entire Tamil Nadu is under the grip of heavier rains and floods. Don't think I am deviating from drought to flood. It is the pathetic plight of Tamil Nadu farmers. One suffering, after another has been thrust upon them by the nature. It is the duty of both the State and the Central Governments to come to their rescue. In some parts of Tamil Nadu, heavy damages have been reported in tanks and irrigation channels in Kanyakumari. Big tanks have breached and bridges and channels have dislocated the irrigation system, so the farmers in those areas are in peril and distress. Help must be extended to them in time. In this connection, I thank the Central Government which has released a grant of Rs.228 crores to Tamil Nadu. A high-level committee under the Chairmanship of our Deputy Prime Minister, Shri L.K. Advaniji, announced a grant of Rs.1,976 crores as relief funds to these 15 States affected by severe drought. As far as Tamil Nadu is concerned, a high-level committee under the leadership of Shri Joginder Singh visited the drought affected areas and submitted a report.

Sir, I request the Central Government to come to the help of the poor farmers always. In this connection, I recommend waiving of all the loans given to the agriculturists in toto and giving liberal loans for raising their crops. Crop insurance scheme alone can save them in times of crisis. Therefore, I urge upon the Government to see to it that the crop insurance to the farmers is made compulsory as this would come to the rescue of the farmers in their distress times. At this juncture, I thank the hon. Prime Minister who has announced a grant of Rs.10,000 crores as relief fund apart from the relief fund already announced. I request the State Governments and the Central Government to appoint monitoring committees at the district

level which should include the people's representatives both from Legislature and Parliament. I also thank the Prime Minister for constituting a high-level committee under the leadership of our Deputy Prime Minister to link all the rivers. It is a laudable scheme and I request the high-level committee to fix a time-limit for the completion of this scheme. I also request them to start the work on the Southern Grid and the Northern Grid simultaneously and, finally, link the two Grids. I would again urge upon the Government to fix a time-limit for this so that the work on the project is immediately started. I am given to understand that this would require 5,00,000 crores of rupees over a period of five to seven years. But I don't think it would be difficult to allocate these funds in the given the time period of five-seven years. Moreover, our hon. Prime Minister has announced that there will be no difficulty in allocating the funds. Sir, once again, I request the State Governments and the Central Government to be with the poor farmers so that the farmers can build a new India. With these words, I conclude.

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सदन में आज देश की सबसे प्रमुख और विकराल समस्या सूखे पर चर्चा हो रही है, जिस पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपकी हृदय से आभारी हूं ।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह आम जनता के पेट से जुड़ी हुई समस्या है । जिस देश में अनाज के पर्याप्त भंडार भरे हों, जहां के किसान अथक परिश्रम करके अनाज का अपूर्व भंडारण कर रहे हों, उस देश के प्रदेशों में सूखे की समस्या और सूखे के कारण भूख से मौतें हों, यह हम सबके लिए बड़ी शर्मनाक घटना है । दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, हम सब लोगों को मिल-जुलकर एकजुटता के साथ इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है । एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का यह विषय नहीं है और समय भी नहीं है, लेकिन जब राज्य में ऐसी विकट समस्या व्याप्त हो और राज्य सरकारें इस पर लापरवाही बरतें, जनता को भ्रम की स्थिति में रखें और भूख से हो रही मौतों को बीमारी से हुई मौत बतायें, इस विषय पर ही बहस में उलझी रहें तथा अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए केन्द्र पर दोषारोपण करें, यह उचित नहीं है । इस विषय को हम सबको गंभीरता से लेना चाहिए । सूखे से सबसे ज्यादा परेशानी गरीब और कमजोर वर्ग को होती है । न उनके लिए पीने का पानी है, न सफाई की कुछ व्यवस्थाएं हैं । गंदा पानी पीकर, सफाई से वंचित गरीब तमाम बीमारियों के शिकार होते हैं । इस साल वर्षा न होने के कारण और गरमी पड़ने के कारण और अधिक बीमारियां चारों तरफ फैलीं । मध्य प्रदेश में 17 नगरों में पांच दिनों में एक बार पानी आ रहा है । मैं ग्वालियर की रहने वाली हूं, वहां दो दिनों में एक बार पानी आ रहा है । इसके साथ-साथ मंदसौर, नीमच, जावरा, रतलाम, शाहजहांपुर, राजगढ़ जो स्वयं मुख्यमंत्री का इलाका है, छिंदवाड़ा, धार, इंदौर, झाबुआ, देवास, सिहोर, सागर, दमोह, टीकमगढ़, इन सभी जिलों की नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में भयंकर पेयजल का संकट है । इन नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों के 75 स्थान ऐसे हैं जहां पर लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं । आज के अखबार की खबर है कि नीमच जिले के मनसा में 12 दिनों के बाद आज पानी आया है ।

महोदय, हम यह जानते हैं कि हर वर्ष कहीं न कहीं देश के किसी न किसी भाग में सूखा पड़ रहा है । यह सब जानते हुए भी राज्य सरकारें समय रहते उससे निपटने की योजनाएं नहीं बनातीं । कहां-कहां सूखे से प्रभावित क्षेत्र हैं और कहां क्या व्यवस्था करनी चाहिए, इसकी समुचित योजना समय से पूर्व ही राज्य सरकारों को करनी चाहिए । लेकिन केन्द्र सरकार से सूखा राहत के लिए केवल मांग की जाती है । राज्य सरकारों के पास सूखे से निपटने के लिए कोई कारगर योजना नहीं है । अन्न के वितरण के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है । सूखे से प्रभावित लोगों को ठीक से अन्न पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है जिसके कारण इस तरह की समस्याएं और विकराल होती जा रही हैं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि राज्य सरकारों के पास इससे निपटने के लिए न तो कोई प्लान है और न कोई ब्लूप्रिंट है । अभी मध्य प्रदेश की बात यहां हो रही थी। मैं यह कहना चाहूंगी कि सितंबर से तो वे अनावरी का काम शुरू करते हैं और जनवरी तक यह काम समाप्त होता है । इस बारे में विरोधी दलों की कोई बैठक नहीं बुलाई गई । सांसदों के पास अभी तक इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है जब कि इसके लिए मिल-जुलकर प्रयास होने चाहिए । इसके लिए मिल-जुलकर प्रयास करने के बजाय हम लोग एक-दूसरे पर दोषारोपण करने में लगे हुए हैं ।

महोदय, अभी हमारे एक सांसद ने कहा कि मध्य प्रदेश ने सूखे से निपटने के लिए दो लाख टन अनाज की मांग की थी और अभी तक केवल एक लाख टन अनाज उन्होंने उठाया है । उन्होंने कहा कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं हैं, इसलिए हम अनाज नहीं उठा सकते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्ट की फ्री व्यवस्था रेलवे के द्वारा की जाए । लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यहां ट्रांसपोर्ट का सवाल नहीं है । राज्यों के पास जो अनाज के भंडार भरे हुए हैं, उसे गांवों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तो राज्य सरकार को उठानी ही होगी लेकिन राज्य सरकार उस जिम्मेदारी को भी अपने कंधों पर लेने के लिए तैयार नहीं है ।

महोदय, मेरे पास एक रिपोर्ट है कि मुरैना में मरा गांव में भूख से मौतें हुई हैं, वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम गई । वहां सुघरा नामक एक आदिवासी महिला ने उनसे कहा कि आप गांव का सर्वे करने आए हैं और केवल एक परिवार को देखकर वापस जा रहे हैं, जब कि पूरे गांव में भूख से तबाही मची हुई है और भूख से मौतें हो रही हैं । वहां एक आदिवासी महिला आनंदी से कहा जा रहा है कि टी.वी. चैनल के सामने आप साक्षात्कार दें और यह कहें कि ये मौतें बीमारियों से हुई हैं, भूख से नहीं हुई हैं । यानी कि ये अखबार * हैं, प्रैस * है, मीडिया * है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया * है ? लोग वहां पर घास की रोटियां खा रहे हैं। खर-पतवार नाम का एक पौधा होता है जिसमें चारों तरफ कांटे लगे रहते हैं । उसके पत्तों को उबालकर और उसमें आटा मिलाकर वहां के लोग अपना और अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं । और ग्रामवासी खुद कह रहे हैं कि आनन्दी आदिवासी महिला ने खुद कहा है कि मैं अपना बयान क्यों दूं, हम तो खुद घास खा रहे हैं। तो इसमें कहने और सुनने की क्या बात है। वर्षा नहीं हुई है, घर में अनाज नहीं है, पानी नहीं है पेट भरने के लिए, हम घास नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। वह थोड़ा सा आटा ले आते हैं तथा घास को उबालकर उसमें आटा मिलाकर तथा

* Expunged as ordered by the Chair.

उसके लड्डू बनाकर वह अपने परिवार को खिला रहे हैं। यह हाल है वहां का और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि वहां जो मौतें हुई हैं वह बीमारी से हुई हैं, भूख से मौतें नहीं हो रही हैं। मेरे पास अखबार की एक रिपोर्ट भी है जिसमें मध्य प्रदेश के स्वास्थय मंत्री खुद कह रहे हैं कि यह बयान असत्य और भ्रामक है। वह जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश के जो प्रभावित क्षेत्र हैं, 28 अक्तूबर के पहले, आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने और अनाज वितरण करने की दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या कार्रवाई की? उपसभाध्यक्ष महोदय, यह वहां के शासन से पूछा जाना चाहिए। जबकि वहां के स्वास्थ मंत्री से पूछा जाता है तो स्वास्थय मंत्री का जवाब होता है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो सरकारों द्वारा किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, लोग मर रहे हैं, त्रस्त हैं और वहां अक्तूबर तक रोजगार उपलब्ध कराने, अनाज वितरण करने की दिशा में सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और स्वास्थ मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि उन्हें इसके बारे में काई जानकारी नहीं है। इस तरह से दोषारोपण करने से काम नहीं चलेगा। इसी तरह से बतलारपुर में जहां भूख से मौतें हुई हैं चार दिन के अंदर प्रशासन के द्वारा वहां एक वीडियो कैसेट बनाया गया और रातों-रात गांव की तस्वीर बदल दी गई। गांव में जो कच्ची मड़इया हैं, कच्चे मकान हैं उनकी पुताई करवा दी गई और साथ-साथ वहां लोगों के घरों के सामने ट्रेक्टर खड़े कर दिए गए यह दिखलाने के लिए कि वहां गांव में सम्पन्नता है तथा लोग भूख से नहीं मरे हैं। जब वहां प्रेस की टीम पहुंची तथा वहां के ग्रामवासियों से पूछा गया कि यह ट्रेक्टर आपके हैं तो उन्होंने बताया कि हमें तो पता नहीं है, कोई आकर खड़ा कर गया है। यह अखबार गलत बोल रहे हैं, प्रेस वाले गलत बोल रहे हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के पास आज की तारीख में 400 करोड़ का एलौटमेंट का पैकेज है, 70 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया है। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का पैसा पड़ा हुआ है। पहले आप ग्रामों में सड़क का कार्य क्यों नहीं शुरू कराते हैं, आप मजदूरों को क्यों नहीं रोजगार देते हैं जिससे कि वह अनाज खरीद कर अपना पेट भर सकें। ऐसी कई स्कीमों का पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है। आप अपनी मशीनरी को तो ठीक करिए, राज्य की मशीनरी ठीक करिए। वहां की व्यवस्था ठीक नहीं है जबकि दूसरों के ऊपर हम दोषारोपण कर रहे हैं। बी0पी0एल0 की स्कीम के तहत एक यूनिट को एक महीने के अंदर 35 किलो अनाज दिया जाता है। वह भी प्रोपर नहीं बंट रहा है। आपके पास बी0पी0एल0 की स्कीम के तहत कौन से परिवार हैं इसकी सूची भी आपके पास नहीं है तो आप एलौटमेंट कैसे करेंगे। तो राज्य की सरकारों से सूची मांगनी चाहिए। केवल केन्द्र पर दोषारोपण करने और यहां चर्चा करने से काम नहीं चलेगा। पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम - सार्वजनिक वितरण प्रणाली राज्यों के अधीन है। उपसभाध्यक्ष महोदय, राज्य उसे नजरअंदाज करते हैं तथा उसको पूरा महत्व नहीं देते हैं। आज सूखे ने जो विकराल रूप धारण किया है उसके पीछे कारण यही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही है, उसकी ठीक से व्यवस्था नहीं हो पा रही है। गोदामों में अनाज बहुत है, केन्द्र सरकार और देने के लिए तैयार है लेकिन राज्यों के पास वितरण प्रणाली कमजोर होने के कारण अनाज सूखा प्रभावित लोगों को नहीं पहुंच रहा है। इसलिए समस्या केवल राशि की नहीं है। केन्द्र सरकार राशि भी देने और अनाज भी देने के लिए तैयार है, लेकिन आप अपना सिस्टम तो ठीक करिए, आप अपनी मशीनरी तो ठीक करिए, अपनी व्यवस्था तो ठीक करिए। कुछ सांसद तो अपनी हाथ में कैसेट भी लेकर आए हैं यह दिखाने के लिए। मैं यह पूछना चाहती हूं कि वह इससे क्या यह सिद्ध करना चाहते हैं कि यह सारी मौतें बीमारी से हुई हैं, भूख

से नहीं हुई हैं। तो मैं यह पूछना चाहती हूं कि अगर यह सारी मौतें बीमारी से हुई हैं तो इसका मतलब यह है कि जो यहां बहस हो रही है, राज्य राशि की डिमांड कर रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां बीमारी से मौतें हुई हैं, वहां सूखा नहीं है। यानी हम यह मान लें कि राज्यों में सूखा नहीं है, बीमारी से मौतें हो रही हैं, भूख से मौतें नहीं हो रही हैं। हमारे इंतजामात खराब हैं, इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। कई सदस्य टेप लेकर घूम रहे हैं, जो प्रेस कह रही है, जो इलेक्ट्रानिक मीडिया कह रहा है, यानी ये सब के सब हैं। इसका मतलब तो यह है कि हम यह मानकर चलें..।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : मैडम, *शब्द अनपार्लियामेंट्री है। जहां-जहां पर * शब्द आया है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्रीमती माया सिंह : सर, आई एम सॉरी। मेरा मतलब गलत बयानबाजी करने से है। मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रेस, अखबारों की तस्वीरें, परिवार की तस्वीरें, परिवार के लोग घास उबालकर खा रहे हैं, घास के लड्डू खा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, मौत हो रही हैं, यह सब दिखाया जा रहा है, क्या प्रेस भी गलत बयानबाजी कर रहा है, गलत कह रहा है?

उपसभाध्यक्ष जी, कुल मिलाकर मैं इन सब बातों के जरिए से कहना चाहती हूं कि केन्द्रीय सरकार, ग्रामीण मंत्रालय, अन्न मंत्रालय द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का जो पैसा केन्द्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा दिया जा रहा है तो इस समस्या पर काबू पाया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को भी अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करना चाहिए। जो प्रभावित परिवार हैं, उन प्रभावित परिवारों को अनाज का वितरण सही ढंग से होना चाहिए। इसके साथ-साथ जो सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है और काम के बदले जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं पर काम प्रभावित गांव में और प्रभावित स्थानों पर सही ढंग से और ईमानदारी से होना चाहिए। हम सभी को मिलकर, राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर इस विकराल सूखे की समस्या का समाधान करना चाहिए। सूखे की समस्या से पूरा देश जूझ रहा है, हमें इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस समस्या से निजात पाने के लिए प्रभावित परिवारों की मदद करने के लिए मिल जुलकर काम करना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

SHRI N.R. DASARI (Andhra Pradesh): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. I would like to confine myself to only two or three problems pertaining to the drought situation, prevailing, more or less, at the national-level, that is, in many States.

For the first time after Independence, we are faced with a drought situation in almost half the country, either in terms of the population or in terms of the geographical area. Of course, the drought situation is not uniform in all the States. It has got its own vagaries also. In some States

* Expunged as ordered by the Chair.

that have been hit by drought, during the course of the monsoon season, they got some rains, but it was not of much use. Therefore, the Central Government should now think on how to meet the alarming situation, which should be treated as 'a national calamity.'

I would only request the Centre to try to help all the States that have been faced with drought, though they have been hit in an uneven manner. It should also consider the gravity of the situation in each of the States. The Government should come forward to help them on a war-footing.

In fact, in our State, the situation is more serious. Out of the 22 districts, actually, 19 districts have been very severely affected by the drought. This year, according to a report that appeared on the 18th, on the eve of our Parliament Session, in the Business Standard, the Rabi croped area would be a mere 8.27 lakh hectares, as against the normal 34.65 lakh hectares; the dry crop area coverage would be only 7.97 lakh hectares, as against the normal 21.8 lakh hectares. In monetary terms, the loss in kharif crop output has been estimated as Rs.3,226 crores, with Rs. 1,887 crores being on account of foodgrains, Rs.647 crores in the case of oilseeds, and Rs.692.5 crores in the case of cotton. This is, in brief, the position. There is so much that has been reported in the Press, which I don't want to go into.

In respect of helping the States immediately, the Central Government is taking certain steps, which I consider as an eyewash. The need of our State is a minimum of Rs. 1,000 crores. But the Centre has given only Rs.170 crores. The need of the State, so far as foodgrains are concerned, is 15 lakh tonnes of rice, whereas the Government has offered only 5 lakh tonnes. Even of this, only 3 lakh tonnes have been provided so far. We also demand that all the loans be waived, particularly of the poor peasants and the middle-peasants.

Now, much is being talked about the Ganga-Cauvery Project, and the nationalisation of rivers. With due respect to the Prime Minister, I would like to say that the statement he made yesterday in the Lok Sabha is nothing but diversionary. It is totally diversionary. When the people are suffering because of drought, and hunger is staring at the face of the people in rural India, he is speaking about the Ganga-Cauvery, linking of rivers, etc., which is neither feasible from the monetary point of view nor practical on the ground.

On the other hand, if the Central Government were to be kind enough to come forward with Rs.5,000-6,000 crores of assistance, we can have the best possible results in our State, by constructing projects on the Godavari, 80% of which flows into the sea, going waste. I request you consider it. The proposal for nationalisation of rivers and the Ganga-Cauvery project are nothing but diversionary. The Central Government should come forward to help the States immediately, to meet the situation that has arisen because of the serious drought in 14 States. Of course, it is for the Centre to assess how to distribute the funds. I don't want to compare one State with the other. I, once again, would request the Central Government to reconsider the plan on meeting this national calamity.

Thank you, Sir.

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Thank you. Sir, it is most unfortunate for our nation that, today, we are suffering from an unprecedented drought in the country. Perhaps, if you compare the past two decades, our country had never suffered so badly in the past. Almost all parts of the country, particularly, the 14 States, are suffering. I agree with our friend, Dasariji, on in what lies the solution. Merely speaking in Parliament or just finding fault with each other is not going to help. On the one side, there are floods, and the water is going waste. On the other, because of drought, we are suffering. On account of this, we are going to have very serious problems. My request to the Central Government, therefore, is, they must have a plan/programme on how to conserve the flood waters, by concentrating on constructing more and more projects. They must make more funds available. Then only the drought can be controlled, the floods can be controlled, and by this, we will be doing a great service to the country.

If we take Rajasthan, Rajasthan is suffering miserably; it is in a very bad shape. Assistance for it is very less. Recently, when the All India Congress President, Smt. Sonia Gandhi, visited the State, she pleaded with the Central Government to give more assistance to Rajasthan, which is suffering, which she has seen with her own eyes. But, in this connection, a misunderstanding is there with regard to Andhra Pradesh. An impression is created that because she objected giving more money to Andhra Pradesh, the Andhra Pradesh Government could not get more funds. It is totally wrong. I would like to clarify this point before this august House. She never said, "Don't give more money to Andhra Pradesh." The Congress Party has

denied it. The State Government is wanting Rs.1810 crores, immediately, from the Central Government. But they gave only Rs.170 crores. I agree with our friend when he demands Rs.1800 crores. It is not right to say that the Congress Party or Smt. Sonia Gandhi objected to it, and, therefore, the Central Government didn't give that much money to Andhra Pradesh. It is not correct.

For Andhra Pradesh, a major setback came when the inflow of waters into the Nagarjuna Sagar, the Nizam Sagar, the Srisailam Dam, the Singoor Dam, and the Tungabhadra Dam suffered. It has to come from Karnataka and Maharashtra. This time, because of drought in those States also, there was no inflow into these dams. As a result, Andhra Pradesh has become a victim of not only the drought in the State, because of lack of rains, but also the non-inflow of water into its various reservoirs.

Also, more importantly, because of drought, instead of 13 lakh plantations, which is the normal every year, we could have only 7 lakh plantations in important parts of Andhra Pradesh. Also, with regard to minor irrigation, almost all the tanks have become dry. As a result, in almost 15 lakh acres, there could not be any plantation. This problem is also there. The borewells have become dry. For the medium irrigation projects, there is no water. I need not repeat. Already, my friends have said about this.

In sum, I say that Andhra Pradesh, to which we belong, is suffering very badly. The people of Andhra Pradesh, the Congress Party, once again request the Central Government to release, immediately, the money as sought by the Government of Andhra Pradesh, *i.e.*, Rs. 1810 crores. Then only one can say that the Central Government is doing justice for the people of Andhra Pradesh.

Recently, all the Ministers of the State Governments met the Finance Minister, Shri Jaswant Singh. They explained the problem. Still, it is at the 'thinking-level' only. I request the Government that in the coming Budget, it must provide sufficient money to meet the challenge of drought. It must work on a war-footing. Also, in the future Budgets, when they take money from institutions like the Asian Development Bank or the World Bank or the international organisations or the Japan Bank, they must give priority to constructing, immediately, some irrigation projects in India, in various States. The Ganga-Cauvery link is only a dream project. It might need, perhaps, lakhs of crores of rupees. We will be happy if it comes about. Immediately, what they must do is, let them concentrate on constructing

irrigation projects all over India, in different parts, allocating Rs.20,000 crores in every year's Budget, so that this unprecedented drought doesn't affect us. Drought is nothing new for the country. This time, we had drought in fourteen States. Some other year, some other States may come under its grip..

In other words, India is facing floods on the one hand; on the other, it is having drought. Some States this time and some other States next time. This unfortunate thing is chasing us continuously. To mitigate this, mere debates, mere speaking, mere finding fault with one another will not help. The real solution lies in Government's action. They should immediately come out with a White Paper on what their strategy is to meet the recurring floods and drought.

Thank you, Sir.

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (हरियाणा): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि सूखे जैसी ज्वलन्त समस्या पर बोलने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया । मान्यवर, दैविक आपदा कभी भी और कहीं भी आ सकती है परंतु अफसोस यह है कि इस भयंकर दैविक आपदा को हल्के तरीके से लिया जा रहा है । महोदय, किसान के साथ मज़दूर भी तबाह हुआ और यही नहीं, क्रय शक्ति समाप्त होने के बाद, जब नब्बे सैकड़ा लोगों की क्रय शक्ति समाप्त होगी तो बाज़ार भी प्रभावित होंगे । हमारी सरकारें शायद प्रभावी कार्यवाही नहीं कर पाईं। मान्यवर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जो बयान सम्मानित सदन लोक सभा में दिया, वह पढ़ा और जानकर प्रसन्नता हुई कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सूखे जैसी गंभीर समस्या पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पहले अपने कृषि मंत्री जी को रोकें। माननीय कृषि मंत्री जी राजस्थान में गए, प्रदेश राज्य सरकार के खिलाफ बोले, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गए और खुलकर कह कर आए कि सूखे पर हम किसान की कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। यही नहीं, हिसार में जाकर इस देश के उस प्रदेश सरकार के खिलाफ बोलकर आए, जो केवल किसान हितैषी सरकार है। हरियाणा सरकार के बारे में यह कहा गया कि उन्होंने अब तक मांगपत्र नहीं भेजा। मान्यवर, कितनी गंभीर बात है कि माननीय कृषि मंत्री जी के यहां से जो जवाब इसी सदन में मिला, उस जवाब में उन्होंने स्वीकार किया कि हरियाणा ने 1895.18 करोड़ रुपए की मांग की है। वही कृषि मंत्री एक महीने बाद हरियाणा के हिसार शहर में जाकर कहते हैं कि हरियाणा की तरफ से कोई आवेदन नहीं मिला। यही नहीं, जुलाई में उनकी टीम भी वहां सर्वे करके आई और उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ-साथ इनको केंद्र को भी एलीगेट किया। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन बयानबाजियों की तरफ न जाकर, यह देखें कि किसान का होगा क्या? किसान की मदद के लिए सहकारी संस्थाएं बनीं। मैंने इसी सम्मानित सदन में कहा था कि नेफेड में दलालों का बोलबाला है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि नेफेड में सरसों की खरीद और बिक्री में जो हुआ, गोले की, नारियल की खरीद और बिक्री में जो हुआ, उसको दिखवा लें, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गलत लोगों का बनाया गया । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस भूखे और सूखे किसान की मदद के लिए सरकार से अनुरोध

करना चाहूंगा कि एनसीडीसी को को-आपरेटिव फैडरेशन इसलिए बनाया था कि किसान और कृषि से संबंधित व्यवसाय को मदद करेगी। परंतु उस पर जहां आज तक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बैठाया जाता था, उसका राजनीतिकरण कर दिया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कुछ लाभ अर्जित करके, किस तरह का लाभ अर्जित किया है, आई कान्ट से बट मैं पूर्णतः श्योर हूं कि लाभ अर्जित करके अपने पीएस की पत्नी को उसमें बैठा दिया, जो कस्टम सेवा की हैं। यह राजशाही चला रहे हैं। डैमोक्रेटिक सैट-अप डैमोक्रेटिक तरीके से चलता है। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आज पूरे देश का किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। केन्द्र सरकार का कृषि मंत्रालय प्रधानमंत्री जी की इच्छाशक्ति के बावजूद भी, उपप्रधानमंत्री जी के निर्देश के बावजूद भी कोई टास्क-फोर्स नहीं भेज पाया और न ही कोई वाजिब मदद कर पाया है। मान्यवर, बीमा फसल योजना की बात बार-बार होती रही है और बार-बार चुनाव के समय लम्बे-चौड़े भाषण देकर बीमा फसल की बात कही गई, बीमा फसल की बात तो नहीं हो पाई पर सीटीबीटी कॉटन में सुना है करोड़ों की हेराफेरी हुई है। मान्यवर, सूखाग्रस्त राज्य की मदद के मामले में ये बागपत तक नहीं जा पाए। केवल अखबारों में बयान देने की बात करते रहे। मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। हरियाणा में 1895.18 करोड़ रुपए मांगे और मिला 33 करोड़ रुपया। यूपी ने 7539 मांगा, मिला 60, यह ऊंट के मुंह में जीरा है। इससे होगा क्या? आप जल प्रबन्धन नहीं कर पा रहे हैं। जिस समय यह मुल्क सूखे से पीड़ित था, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानकारी चाहता हूं कि क्या करने गए थे कृषि मंत्री जी रोम में? उनकी रातें या तो यूपी लखनऊ में रहा करती हैं या दिल्ली में रहा करती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मुल्क के 80 करोड़ किसान को किसके भरोसे छोड़ रखा है। गांव की एक कहावत है कि "अनाड़ी की चौधर, बुढ़ापे का ब्याह और घर की सियासत घर को खा जाती है । इस विभाग को बचा लो। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां 40 सैंकड़ा सिंचित क्षेत्र है, 60 सैंकड़ा से ज्यादा असिंचित क्षेत्र है, मान्यवर, भूजल स्तर रोज गिर रहा है, उसका हम कोई प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं। मैं मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, हरियाणा से आता हूं। हरियाणा में एसवाईएल सतलुज नहर बननी थी, जनवरी 2003 तक बनाने की बात हुई। परन्तु अब तक उस पर कार्य भी प्रारम्भ नहीं हुआ है। आप पंजाब सरकार को दबाव नहीं दे पा रहे हैं। क्या होगा, और उसके बाद हरियाणा सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी के बिना रह जाएगा और सियासी लोग इसे दांव में फंसाकर के रख देंगे। इस पर मैं अपका ध्यानाकर्षण चाहता हूं, केन्द्र सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे। महोदय, मेरे यहां उत्तर प्रदेश में हिंडन और कृष्णा नदी का पानी जमीन से तीस फीट नीचे बह रहा है । भूजल का स्तर रोज नीचे गिर रहा है । यह सघन कृषि क्षेत्र है । इसके बारे में केंद्र सरकार को विशेषज्ञों की कोई रिपोर्ट आई है कि आने वाले बीस वर्षों में यह क्षेत्र रेगिस्तान बन जाएगा लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई । मैं चाहता हूं कि इस पर कार्रवाई की जाए। काम के बदले अनाज योजना को निश्चित और सुनिश्चित तरीके से चलाया जाए । महोदय, उत्तर प्रदेश का किसान पहले सूखे से मरा, सूखे से बचकर उसने गन्ने की फसल को उगाया, बहुत कोस्टली सिंचाई करके उसने गन्ने की फसल को बचाया । मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैंने कल भी सम्मानित सदन में कहा था कि जांच होनी चाहिए । हम लोग, जो आरोप लगाते हैं, हमारे भी राजनैतिक चरित्र की जांच होनी चाहिए । हमारे आर्थिक और व्यक्तिगत चरित्र की भी जांच होनी चाहिए । जिनके ऊपर हम जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए । यह बात मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि इसमें पैसा लिया गया है । पैसा लेकर किसान को

बर्बाद करने का काम किया गया है । आज चीनी मिलें बंद हैं । किसान आत्महत्या कर रहा है । ऐसे में हम लोग यहां बैठकर लंबे-चौड़े भाषण देते हैं, बयानबाजी करते हैं । यह औचित्यपूर्ण नहीं है । महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पुनः मांग करता हूं कि क्या कारण थे जब विगत वर्षों में मलतपुर चीनी मिल ने किसान का पैसा जमा करा लिया ? क्या कारण है कि मिल मालिक चार सौ करोड़ रुपये लेकर बैठा है और किसान को पैसा नहीं दिया जा रहा है? क्या कारण है कि जो निजी पचास चीन मिल्स हैं वे यह शगूफा खड़ा कर रही हैं कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे और सरकार की नीति के तहत, प्रदेश सरकार ने जो भाव तय किया है, उसे नहीं देंगे । कहीं न कहीं कोई खोट है । मैं यह बात सीधे-सीधे कहता हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि जिसकी वजह से आप बदनाम हो रहे हैं, वह कारण आपका नहीं हैं । कहते हैं कि जे-जे पांव पड़े संतन के, ते-ते बंटाधार । ये सबसे पहले चंद्रशेखर जी के साथ गए, बहुत बड़ी पार्टी थी, छह स्टेट में राज था, खत्म हो गया, उसके बाद वी.पी.सिंह जी के साथ गए वे भी खत्म हो गए, उसके बाद देवेगौड़ा जी के साथ गए, वे खत्म हो गए, नरसिम्हाराव जी के साथ गए, वे आज मुकदमे झेल रहे हैं । अब आपके साथ राजनाथ सिंह जी ने वकालत की थी, वे बेचारे गद्दी से गए । आपका क्या होगा? बेहतर यही है कि आप दूरी बनाकर रखिए ।

(उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) पीठासीन हुए)

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इस देश को बचाइए । ये उद्योग मंत्रालय में गए, उद्योग तबाह, खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय में गए, वह भी तबाह, कृषि मंत्रालय में जिस दिन आए थे, कृषि मंत्रालय तबाह होना था । आज अगर किसान को बचाना चाहते हो कुछ करिए । खरीफ की फसल चली गई, रबी की फसल नहीं हो पा रही है । किसान को मदद देने का कुछ काम नहीं हो पा रहा है । मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि वह तत्काल हस्तक्षेप करे । रबी की फसल बचाइए । किसान को मुआवजा देना चाहिए । रबी की फसल की बुआई नहीं हो रही है । इसका किसान को मुआवजा मिले । गन्ने का भुगतान हो और जो सूखा पीड़ित किसान हैं उनके आंसू पोंछने का काम हो । मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो को-ऑपरेटिव संस्थान हैं, जो किसानों की मदद के लिए बने थे उनमें नामांकन की प्रक्रिया क्या है ? किस प्रकार के नैफेड में नामांकन किए गए ? सरसों की दो लाख बोरियां खरीदी गईं । रामायण और महाभारत में कहा गया है कि राजा को कभी व्यापार नहीं करना चाहिए । मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो लाख सरसों की बोरी साढ़े बारह सौ या साढ़े तेरह सौ रुपये में खरीदकर रख ली गई हैं । इसमें नैफेड का क्या हाथ है ? नैफेड की उच्च स्तरीय जांच न होने का क्या कारण है ? महोदय, एन.सी.डी.सी. में आई.ए.एस. की जगह, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी की जगह, पी.एस. की पत्नी को बिठाकर राजशाही का परिचय दिया है । इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए । मैं पुनः आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि केंद्र सरकार हरियाणा जैसे कृषि सघन क्षेत्र को अधिक से अधिक 1895 करोड़ रुपये की तत्काल सहायता मुहैया कराए । जिस तरह से हमने बार-बार प्रयास किया है, पत्र लिखे हैं, अनुरोध किया है उसके लिए कार्य करे । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (Kerala): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity to take part in the discussion on the drought situation prevailing in our country. Sir, the drought situation,

throughout this country, has elaborately been discussed in this House and all the hon. Members have expressed that our country is based on agrarian economy. More than 70 per cent of the people depend on agriculture. Therefore, any change in the regular climatic conditions will adversely affect the agricultural production and it will directly hit the Indian economy. So, considering the main focus and importance of the agricultural production and our economic base, or, our stability, it should be given the first priority. So, priority should be given to the management of disasters like floods, drought etc. Even after 50 years of Independence, we don't have a proper disaster management mechanism. We don't have an effective mechanism to deal with situations like floods, drought, cyclone, etc. So, the first point which I would like to submit before this House is that the Government should come out with a clear proposal, a scheme, a project, or a mechanism, to deal with such disaster situations in a proper way, in a time-bound manner. During every session, whether it is the Winter Session, the Monsoon Session, or the Budget session, we discuss the problem of drought, cyclone or floods. After the discussion is over, the Government makes an announcement in the House that so much amount will be given as relief package. In every session, the same thing is repeated. I know we have not been able to prevent these disasters because of the various environment and scientific aspects that have to be looked into. We cannot totally prevent it, but we can manage them properly, in a scientific way. That is why I am suggesting that a long-term plan has to be evolved. This is my first point.

The Indian Meterological Department had declared that in the year 2002 the rainfall, especially, from the South-West Monsoon would be less. It is one of the worst drought-affected years of the Century. So, we can imagine the impact of drought situation on agricultural production. What has been the estimated loss or the estimated decline in agricultural production? It is being estimated that compared to last year, there has been a decline of 18.72 per cent in agricultural production. We have to see how it will affect the Indian economy in the future. We have to take that into account.

My next point is regarding the approach of the Government in dealing with this situation. According to me, the Government of India has remained a silent spectator in dealing with this disaster. About 16 States have been completely affected by drought. Suicides by farmers, starvation deaths due to unemployment, deaths due to poverty, everything, is taking

5.00 P.M.

place in the country. I am not going into the details of this because those points have already been covered. The question is: what concrete action has the Government taken to deal with this situation? Nothing is being done by the Government; this can be seen from the figures itself.

Also, we are not able to give any prominence to agriculture, because of the policy being pursued by the Government. What is the economic policy of this Government? We have a policy of liberalization. Only because of this, we are not able to give prominence to agriculture and agricultural production. This liberalization policy aims at the accelerated growth of the industrial sector and the Information Technology sector. It is not concerned with the poor people; with the common people. We all know that more than 70 per cent of the population of our country is dependent on agriculture. Those people are being ignored, and the entire focus or concentration is on the Information Technology sector. As a result of this, no attention is paid at all to management of these disasters like floods, drought etc. This is what has happened. Today, we have a buffer stock of 62 million tonnes of foodgrains. They are lying in the godowns of the Food Corporation of India or the Central Warehousing Corporation godowns. On the other side, starvation deaths, deaths due to poverty, are also taking place. In my State of Kerala also, last month, in the plantation industry, three persons died due to poverty. On the one side, there is bumper production and a huge stock of foodgrains in the godowns; on the other side, deaths due to starvation are also taking place. All this is happening because the Public Distribution System has totally failed. Giving subsidy to the common people, or, to the poor people seems to be out of the agenda of this Government. That is the reason why this is going on. Merely declaring Rs.10,000 crores for the relief measures will not solve the problem. ..*(Time Bell)*.. Sir, I am concluding. I will take only two minutes.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : एक मिनट, अगर सदन की सहमति हो तो इस डिसकशन को आज ही पूरा कर लिया जाए, यद्यपि कृषि विभाग के माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं, उनका स्वास्थ्य खराब है, इसलिए वह तो उत्तर कल या किसी और दिन देंगे, लेकिन डिसकशन के लिए अब केवल चार सम्मानित सदस्य ही बोलने से रह गए हैं, इसलिए जल्दी-जल्दी अगर वह कर लेंगे तो ठीक रहेगा । अगर सदन की सहमति हो तो इस डिसकशन को आज ही पूरा कर लिया जाए ।

श्री दीपांकर मुखर्जी : आपने जब कृषि मंत्री का कहा है तो Sir, very serious charges have been levelled by an hon. Member against the Minister of Agriculture. So, he should come prepared with the reply.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): खत्म कीजिए।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I will conclude in two minutes. So, this policy is being followed by the Government. As a result of this, the contribution of the agriculture to the GDP has come down to 25 per cent. Decades back, the contribution of agriculture to the GDP was 50 per cent. But now it has come down to 25 per cent. As regards the foodgrains production, it is contributing 12 per cent to the GDP. The contribution of agro-based industries, such as textile industry, jute industry, sugar industry, which accounts for a major chunk of our industrial output, to the GDP has fallen sharply. On the other hand, the contribution of engineering industry, chemical industries and Information Technology industry has risen. It is very evident from these factors as to what is the attitude and approach of the Government of India, especially, the Government which is pursuing the liberalised policies, towards agriculture and related matters. As far as relief measures are concerned, it is okay.

Now, I would like to make some suggestions with regard to water conservation and water harvesting. We should have a long-term plan for this. At present, there is a project, namely, the Drought Prone Area Programme (DPAP). This Project is totally based on watershed management. It is my personal experience that Watershed Management Programme is not giving good results, even though the statistical datas given by the Government speak otherwise. I would like to suggest that both the projects, that is, water conservation and water harvesting, should be entrusted to the Panchayati Raj Institutions. They can very well do it. Since it is a Centrally-sponsored scheme, all the powers are vested with the Centre. I suggest that all the rights should be given to the Panchayati Raj institutions.

I would also like to make two points regarding my State. This year, in my State, as compared to the last year, there has been only 49 per cent rainfall. I do not mean to say that there is a severe drought-like situation, except in two or three districts. But the point is the power sector is fully dependent on the hydel power. So, that is being affected. In the case of cash crops, like coconut, rubber, etc. given the present situation, definitely, the agriculture will be affected. I do not want to go into all these details. In Kerala, agriculture produce is also being affected. It is quite unfortunate to note that the State Government of Kerala has not submitted any memorandum or representation to the Government of India for seeking any relief. I regret to say that even the Leader of the Opposition, while

moving the Motion in the other House, did not mention about the State of Kerala. The State of Kerala will be affected in future. Therefore, I would appeal to the Government of India that in this package of Rs.10,000 crores, the State of Kerala should also be included, keeping in view the damage which may occur to the cash crops in future. With these words, I conclude.

श्री वशिष्ठ नारायण सिंह (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, एक गंभीर विषय पर सदन में पहले भी चर्चा हुई है और आज भी हो रही है और जो तस्वीर देश के सामने अभी उपस्थित है उससे मन में कुछ चिंताएं पैदा हो रही हैं । एक ओर बाढ़ और सूखे की स्थिति, और दूसरी ओर यह घोषणा कि सरकार के पास अन्न का पर्याप्त भंडार है और भूख से इस देश में कोई व्यक्ति मरेगा नहीं .... । दूसरी ओर एक ऐसी स्थिति है कि किसान अपनी उपज की उचित कीमत के लिए संघर्षरत हैं जिससे बहुत लोगों के मन में अपने कृषि कार्य को छोड़ने का विचार उठ रहा है ।

महोदय, किसान के अनाज के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, यह बात अपने आप में चिंता पैदा करती है । कई जगह ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि जो अनाज सूखे के वक्त सप्लाई किया जा रहा है, वह स्टेंडर्ड अनाज नहीं है । वह सड़ा हुआ अनाज है । देश के सामने यह एक विरोधाभासी तस्वीर उपस्थित है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस स्थिति से तीन ही वर्ग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं - एक वर्ग है सीमांत किसानों का, दूसरा मजदूरों का और यदि पशुओं को भी एक वर्ग मान लिया जाए तो तीसरा वर्ग है पशुओं का । लेकिन जब भी सूखे की चर्चा होती है तो एक चौथा सवाल भी गंभीर रूप से बहस के रूप में आता है और वह है देश में पेयजल की समस्या । महोदय, पेयजल की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन जब सूखे का वक्त आता है तो पेयजल की चर्चा, भूतल के जल-स्तर की कमी की चर्चा इसलिए व्यापक हो जाती है कि पीने के पानी की समस्या बड़े पैमाने पर लोगों के सामने खड़ी हो जाती है । इसलिए यह समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है और वह इस रूप में गहराई है कि इसे एक दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है कि आजादी के इतने दिनों बाद इस समस्या से निपटने के संबंध में हमारी प्राथमिकताएं क्या हों ? अगर प्राथमिकताओं के आधार पर बाढ़ और सूखे से निपटा गया होता और विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव नहीं होता तो आज बाढ़ का यह स्वरूप और सूखे की यह भयावहता दिखाई नहीं पड़ती । लेकिन हमने इन समस्याओं को प्राथमिकताओं के आधार पर देखने का प्रयास नहीं किया । अब इस प्रश्न पर बहस चल रही है और सरकार को जवाब देना है तो मेरा सरकार से आग्रह होगा कि सरकार तय करे कि देश की 80 प्रतिशत आबादी जिस व्यवसाय पर निर्भर है, उस व्यवसाय को प्राथमिकता के आधार पर यदि टैकल करने का प्रयास नहीं किया जाएगा तो हर साल इसी ढंग से बहस चलती रहेगी और नई-नई समस्याएं पैदा होती रहेंगी । इसलिए प्राथमिकताओं के चयन और कृषि से संबंधित इन समस्याओं को देखने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह मूल समस्या है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बिंदु यहां सुझाव के तौर पर रखना चाहूंगा जिन्हें अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है । मुझे भी उन्हें रिपीट करना है । कई राज्य सरकारों ने अपने यहां स्कीम्स जारी की हैं, लेकिन उनके कार्यान्वयन के बारे में विचार किया जाय तो काफी त्रुटियां

नजर आती हैं । आपने फसल बीमा योजना शुरू की है जिस में तहसील को इकाई बना दिया है, किसान को इकाई नहीं बनाया है । कैलामिटी फंड पर्याप्त नहीं रहने के कारण डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की ओर से आरोप-प्रत्यारोप की बातें चलती हैं । फिर यह आरोप भी लगता है कि अनाज कहां गया, क्यों वह सप्लाई नहीं हो पाया । तो इस तरह के सवाल उठ रहे हैं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आजादी के पहले गांवों में जल व्यवस्था के अंतर्गत पोखर, कुएं और आहर की व्यवस्था थी । महोदय, आप भी जानते होंगे कि आपके प्रदेश और बिहार में जहां सरकारी नहरें नहीं थीं वहां आहर की व्यवस्था थी जिसके चलते वहां सिंचाई की व्यवस्था हो पाती थी । आज उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है । साथ ही इस बात की भी जरूरत है कि हमारे यहां क्रॉपिंग सिस्टम पर ध्यान दिया जाए । माननीय लालू प्रसाद जी ने भी यह बात कही थी और मैं भी उसका पुरजोर समर्थन करता हूं । कृषि विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए । वह है क्रॉपिंग सिस्टम, वह है मोड ऑफ प्रोडक्शन । अगर आपने इस सिस्टम को और पैदावार के सिस्टम को बदलने का काम नहीं किया तो सूखे की समस्या से आप निजात नहीं पा सकते । मरूआ की खेती, बाजरे की खेती और जो कम समय में बीज पैदा हो सकता है, अगर इनकी पैदावार बढ़ाने की कोई योजना नहीं बनाई गई तो यह देश सूखे से प्रभावित होता रहेगा ।

महोदय, आज सूखे से इतने राज्य प्रभावित हो गए हैं । इसलिए अब तो हमको यह देखना पड़ेगा कि कितनी जगहों पर किस ढंग से सिंचाई की व्यवस्था हम कर सकते हैं, जिसके लिए एक बृहत और कारगर योजना बनानी पड़ेगी । मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि एक इफेक्टिव जल नीति बनाई जाए । मैं समझता हूँ कि जब तक यह एक बांधने की और एक जोड़ने की जल नीति नहीं बनाई जाएगी तब तक सूखे की स्थिति का निपटारा नहीं हो सकता है।

महोदय, मैं अंत में आपके माध्यम से सरकार से, इस माननीय सदन से यह अपील करना चाहता हूँ कि सरकार अब प्राथमिकताओं के आधार पर कृषि को, सूखे को, बाढ़ को लेने का प्रयास करे ताकि इस देश की एक बड़ी आबादी को भूख और संक्रामक बीमारियों से बचाया जा सके और देश को आने वाले समय में किसी भीषण संकट का सामना न करना पड़े । आज देश में एक लेबर मार्केट बनने की स्थिति जो पैदा हो गई है, इस लेबर मार्केट को यदि नए ढंग से पैदावार के साथ नहीं जोड़ा गया और कृषि व्यवस्था को ठीक नहीं किया गया तो देश को मझधार में जाने से कोई रोक नहीं सकता ।

महोदय, इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ । धन्यवाद ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : श्री एम0 वी0 राजशेखरन । इससे पहले कि आप अपनी बात रखें, कृपया आप ध्यान रखें कि आपकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी से तीन और माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और आपकी पार्टी के केवल 12 मिनट शेष हैं, इसलिए आपको इसी में समायोजित करना है ।

SHRI M.V. RAJASHEKARAN : I will certainly keep this in view.

Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak. As you are aware, and as it has been brought out here, it has become a permanent feature in India as the drought is occurring very often. Sir, let

me also inform this House that with the change of climate and with the degradation of environment, the drought is going to be more and more acute in the coming years. As one of the agricultural experts has put it, the Indian agriculture is a gamble during monsoon. Taking all these things into account, what is it that we are doing? What is the responsibility of the Government? Sir, I may bring to the kind notice of the Central Government that there is a lack of sensitivity on their part. You can see the irresponsibility and the unaccountability on their part in dealing with this very serious situation. What is needed is the immediate response. We cannot wait for months together. In fact, during the drought, the people who are going to be affected very seriously are the poorest of the poor, because they lack food security. How are we managing the food security and how are we able to provide immediate relief? Now, Sir, if you take these things into account, you will find that there is a total negligence on the part of the Central Government.

Sir, there is a National Calamity Contingency Fund. How is it disbursed? Has it been disbursed with efficiency and speed? As you are aware, many of our colleagues have brought to the notice of this hon. House, how lethargic they have been even in releasing the funds and foodgrains.

Now, I would like to come to some of the very serious points which our Karnataka State is facing. Sir, through you, I would like to inform this insensitive Government that on 24th July, the first request was made by our Chief Minister to the Government of India to look into the serious problem which the State is facing. The memorandum was submitted to them. Later on, the Chief Minister, along with a senior Minister, came to Delhi and met the hon. Agriculture Minister as well as the Prime Minister. Later on, Sir, there was a demand and request made for immediate release of 6 lakh tonnes of foodgrains. Sir, again, on 31.7.2002, it was brought to the notice of the Government that out of 28 districts, 24 districts are under severe drought. Sir, as you are aware, in India, today, nearly two-thirds of the districts are reeling under drought. Similarly, out of 176 talukas in Karnataka, 143 talukas are reeling under drought. Sir, again, on 9.8.2002, the request was made, but, an intimation was received from the Central Government that they have released 2 lakh tonnes of foodgrains. Sir, despite this, the State Government is unable to get the full benefit of it because the Food Corporation of India does not have the required stocks at the district headquarters. In fact, there is an all-round lethargy, one can

see, on the part of the Food Corporation of India. Sir, this situation has to be drastically changed. As one of our hon. colleague just now pointed out, we have got 62 million tonnes of foodgrains stocked in our godowns, but, we are not reach that to the poorest of the poor because our storage facilities are put in the district headquarters, and we are not able to move the stock to the particular area where there is an immediate requirement. Sir, the Government of Karnataka has been reminding, time and again, that they need an assistance of Rs.1,562 crores. What is it that the Government has done? Sir, they cannot sit idle, particularly, at the time of drought, when the people are suffering. We have also seen here that there is so much of discrimination by the Centre, particularly, against Karnataka.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप कृपया समाप्त करें । कृपया समाप्त करें ।

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Sir, I would take only one more minute. I would like to make a couple of suggestions. Sir, my first suggestion is, the Central Government should immediately set up a High-Power Committee or a Task Force, with the Prime Minister as the Chairman, and all the Chief Ministers as its Members. Secondly, the Prime Minister's Office should have a monitoring mechanism to monitor as to how the drought situation is affecting the whole country, and what measures are being taken, and how far those measures are being implemented, with efficiency and speed. Sir, there should be a mechanism and strategy to assess the drought condition from time to time. Let me quote one example. Way back, the United States forecast how the Soviet Union would be coming under drought and what would be its effects. Based on that, their foreign policy was evolved. Sir, today, new technologies have come, and we should see how we can take advantage of it, tackle such situations in future. Sir, our Congress President, Soniaji, has suggested that the National Calamity Fund should be increased to Rs.10,000 crores. Sir, it is a good suggestion. I hope, the Central Government will take immediate action to raise this amount and make available this amount with speed and efficiency, whenever it is required.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : कृपया समाप्त करें ।

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Sir, I am just concluding...*(interruption)*... Sir, again, as you are aware, the crop insurance scheme is in vogue in our country. But, how is it being implemented? Now, we must see at the stage of implementation as to what the problems are, which are there. Sir, in fact, the State Government of Karnataka is pressing

that the crop insurance scheme should be applied in totality, covering all the farmers.

Now, I come to the question of payment of interest on loan, and as you are aware, the State government will not be able to take the entire burden upon itself. The Central Government should come to the help of the State Government. The State Government of Karnataka has already requested that 50 per cent of the interest should be met by the Central Government. But, unfortunately, up till now, there is no response. *(Time Bell.)* Sir, I am just concluding. I will take half a minute. My next point is regarding the godowns. As I have already stated, the godowns of the Food Corporation of India should be evenly spread throughout the country, particularly, in the rural areas, so that whatever foodgrains are going to be made available to help the drought-prone areas, they will be able to take advantage of.

Lastly, in the Central Government, we have got the Drought-Prone Areas Programme. I have not been able to understand how far that programme has been successful, and what has been its impact. If it needs improvement, what strategy is the Central Government adopting? With these words, I would like to take this opportunity to thank you, and I hope, the Central Government will become more sensitive, more responsive and more acocuntable in future. Thank you.

श्री शंकर राय चौधरी (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन में भी अकाल और सूखे की समस्या पर चर्चा हुई थी, अभी तक हो रही है और मैं यह चर्चा सुनता आ रहा हूं । इसमें तकरीबन वही अलफाज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो पिछली बार इस्तेमाल किए गए थे । महोदय, सूखा हमारे देश में कोई नयी बात नहीं है लेकिन अभी जो सूखा पड़ा है, उसमें याद रखने की बात यह है कि 11 साल के अच्छे मानसून के बाद इस साल मानसून की जो रफ्तार है, उसमें तब्दीली आई है । जहां बारिश आनी थी, वह देर से आई और इसकी वजह से जो हमारी कृषि व्यवस्था है, उस पर बहुत असर पड़ा है ।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सूखा आता है तो वह अचानक नहीं आता है, वह अपने संकेत देकर आता है । इस साल भी जो सूखा पड़ा है, इसके संकेत हमें बहुत पहले से मिल रहे थे । सबसे पहले जो शीतकालीन वर्षा होती है, वह इस साल नहीं हुई । उसी समय हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए था । उसके बाद साल के शुरू में हमारा मौसम विभाग मानसून का जो फोरकास्ट करता है, उसमें उनके 23 पैरामीटर होते हैं और वे करीब-करीब सही फोरकास्ट करते हैं कि इस साल वर्षा कैसी होने वाली है । वर्ष 2002 में जब मौसम विभाग का फोरकास्ट आया तो शुरू से ही वे कह रहे थे कि 23 पैरामीटर में से 6-7 पैरामीटर पूरे नहीं हैं । इसलिए हम आज जो सूखे की स्थिति देख रहे हैं, यह अचानक हमारे ऊपर नहीं आई है । इसके लिए हमें बहुत पहले ही तैयार रहने के संकेत मिल गए थे लेकिन हम तैयार नहीं हुए ।

महोदय, अभी यहां जो बहस चल रही है, इस बहस का असली मुद्दा यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है - केन्द्र सरकार जिम्मेदार है या राज्य सरकार जिम्मेदार है ? इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं । स्टेट गवर्नमेंट की कुछ जिम्मेदारियां हैं और केन्द्र सरकार की भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं । और मेरे ख्याल से जैसे जैसे हमने इस सूखे पर कार्रवाई की है दोनों व्यवस्था में काफी खामियां नजर आई हैं। अफसोस की बात है कि जो यह सूखा आया है इसमें भी हमारे कई प्रदेशों में, कई सूबों में और केन्द्र सरकार के बीच जो राजनीतिक सरगरमी है वह इस बहस में दिखाई दी है। यह अफसोस की बात है। क्या-क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए यह बात माननीय सदस्यों ने बताई है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं खास बात पर ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि जब भी हमारे ऊपर कोई आफत आती है तो एक लफ्ज बार-बार इस्तेमाल किया जाता है जो एक किस्म का तकिया कलाम बन जाता है वह है वारफुटिंग। चाहे वह बाढ़ हो या सूखा उसके साथ जूझने के लिए हर सरकार, हर पौलिटिकल पार्टी कहती है कि यह जो हमारे ऊपर आपत्ति आई है इसके साथ जूझने के लिए वारफुटिंग में आया जाए। तो यह वारफुटिंग सिर्फ शब्द रह जाता है। जो वारफुटिंग चीज होती है, अभी हमने पिछले साल के आखिर में देखा है कि जब हमारी फौजों को आगे बोर्डर पर ले जाया गया था तो जैसी कार्रवाई की गई थी उसको वारफुटिंग कहते हैं। तो आखिर में करना क्या है। अब लम्बे अरसे से हम प्लान बना रहे हैं, प्लान बनते आए हैं, वह प्लान बने नहीं हैं। अभी यह जो गारलैंड कैनाल है नदियों को जोड़ने का यह हुआ नहीं है, यह होना चाहिए था। हुआ नहीं है क्योंकि पैसे नहीं है या कई वजहों से हुआ नहीं है। यह बनते-बनते अरसे हो जाएंगे। जो हमारे पास गांवों में कुएं हैं और पोखरें हैं तो इनकी सफाई की बात बहुत सालों से हो रही है। इनको हम लोगों ने किया नहीं है। इनको भी हमको करना चाहिए। लेकिन जो इमीडिएट एक्शन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को लेना चाहिए वह वारफटिंग में करना है। लेकिन चाहिए क्या? जो वहां के बाशिन्दे हैं उनको अनाज चाहिए, जो वहां के मवेशी हैं उनको चारा चाहिए और दोनों को पीने का पानी चाहिए। यह तीनों चीजें अगर उनको वहां मौजूद हो जाएं तो जो चपेट में आते हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा आघात तो होता ही है लेकिन उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इन तीनों बातो पर अगर हम वारफुटिंग पर काम करें तो मेरे ख्याल से जो काम होना चाहिए था जो असर पड़ा है उस पर कुछ न कुछ तबदीली आती। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कहती हैं कि हम लोगों ने अनाज दे दिया है, स्टेट गवर्नमेंट ले नहीं रही है। स्टेट गवर्नमेंट या तो कहती है कि हमें मिला नहीं है या जो मिला है वह सड़ा हुआ है। इसमें सच क्या है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह कैसे हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट बार-बार कहती है कि इतने करोड़ रुपए चाहिए, इतने लाख टन अनाज चाहिए और जो सेंटर होता है वह कम देती है। हिसाब किसका ठीक है? सेंटर का ठीक है या प्रदेशों का ठीक है और यह जो हमारे यहां पर बहस चलती है इसमें हमारी जनता और जो जीवन दायक प्रसाधन हैं, वह खत्म हो जाते हैं। अभी कहते हैं कि वहां मुखमरी से मौते हुई हैं। जहां मौतें हुई हैं और जिस तरह की वहां राजनीति है वहां के लोग कहते हैं कि यह तो भूख से नहीं मरे हैं, यह बीमारी से मरे हैं। एक और बात जो दुखद् बात है वह कहते हैं कि यह तो भुखमरी की मौत नहीं है यह तो मेलन्यूट्रिशन से मरे हैं। दोनों में फर्क क्या है? क्या हम लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने के लिए यहां बैठे हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि प्रसाधन हमारे पास है, जो प्रशासनिक मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वह हमारे पास है और जो सरकारी मुलाजिम हैं मैं समझता हूं कि तकरीबन-तकरीबन काबिल हैं। लेकिन वह सब होने के

बावजूद यह नुख्स कहां पर है, वह हम निकालें। बाकी जो हमारे लम्बे अरसे के प्लान हैं वह होते रहेंगे, नदियों को जोड़ेंगे, पोखरें बनाएंगे, कुंए खोदेंगे, सड़कें बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अभी जो जनता मर रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि अचानक यह हमारे ऊपर आपत्ति नहीं आई है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग जो काउन्सिल आफ स्टेट्स हैं, राज्य सभा के सदस्य हैं, कुछ सदस्य सरकार में हैं, कुछ विपक्ष में हैं, हम एक दूसरे से सलाह लें और सलाह लेकर बतायें कि हमारे इस आपातकाल में, जो आपदा इस साल आई है, अगले साल परमात्मा न करें, यह आये, लेकिन कुछ साल बाद आयेगी जरूर। इसलिए हमें राजनीति से ऊपर उठकर एक नई पहल करें। हम कहते जरूर हैं कि हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। इस बात को हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, उसको ठीक से काम में लगाया जाना चाहिए और जो इमीडिएट एक्शन लेना है, अनाज, चारा, पानी उपलब्ध कराना है, उसके लिए फौरन जो प्रबन्ध हम कर सकते हैं, उसको वाकई में वार-फुटिंग में किया जाए। धन्यवाद।

SHRI R.S. GAVAI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very thankful to you for allowing me to speak. I will be very brief. The drought situation prevalent in the nation is a matter of great concern to all of us. It is a national problem. This problem does not relate to the States alone. Subjects like floods and drought should be discussed above politics. Cutting across party lines, we should raise issues like this. I will do that within a span of three or four minutes, giving some useful suggestions.

Sir, as I mentioned earlier, a wider part of the nation is suffering from the unprecedented drought situation. When you spoke on this issue, you had referred to both, drought and floods. सूखा भी है, बाढ़ भी है। They are two sides of the same coin. We cannot split them. I will deal with that also.

At the outset, I would like to point out that various States are suffering from the drought situation. Some States, like Rajasthan, are severely suffering. Some States are partially suffering. I would like to make certain suggestions regarding my State, Maharashtra. In my State, roundabout 10,000 villages are affected by the drought situation. The number of persons registered under the Employment Guarantee Scheme is five lakhs. Of course, the main after-effect of drought is water-scarcity, shortage of drinking water. For purposes like providing jobs to the agricultural workers and having an alternate crop system, the State requires funds from the Centre. Sir, I want to make it amply clear that neither the State nor the Centre should shirk responsibility to deal with the problem of drought, shifting the burden on each other. The Government of Maharashtra has requested the Ministry of Agriculture for releasing a grant of Rs.500 crores from the Calamity Relief Fund to meet the drought

situation. The allocation is to be made from the CRF. It may be rather a new concept. I am highly impressed by the views of Premachandranji who has dealt with this subject basically. I would say that the basic problem is concerning with agriculture. The basic subject is agriculture. The drought, floods, etc., are caused due to negligence, and agriculture has been neglected for the last 52 years. Why, Sir? This is the key industry, the basic industry, the core industry, of the nation. We say that our economy is agricultural economy, monsoon economy and village economy. Eighty per cent of the population in the country depends on agriculture. Such a basic industry, key industry, is being, unfortunately, neglected, and that is why we are affected by the aftereffects of drought, floods and everything. So, how to deal with them? As far as dealing with the drought situation is concerned, many previous speakers have made suggestions. Now, what do you mean by the drought-prone area? It is an arid area. We have not yet done full justice to the drought-prone area. As I have mentioned earlier, there is no proper water management, whether it is a big reservoir or a small reservoir or a tank or a medium project or a big project. But, now, the problem is that of conservation of ground water. As Laluji has mentioned, even the ground water has gone down very much. Now, you have to recharge the ground water. That will help the agriculture and also solve the drinking water problem. Now, I don't want to speak at length about water management, because the time at my disposal is very short. But the fact is we never bothered about water management. We never bothered about the crop pattern. The whole problem of our nation is that hardly about 20% of our agricultural land is irrigation-based, and 80% is dry-land cultivation. Laluji mentioned a point, whether we are thinking of a crop pattern, dry-land farming, whereby we could increase our production. As I mentioned earlier, the National Water Scheme was not duly considered. This was the scheme submitted by Sir Visvesvaraya and Dr. Baba Saheb Ambedkar. The total expenditure at that time was Rs.5,000 crores. Now we have to spend Rs.1 lakh crore. So, an inter-connection of the northern and southern rivers will solve both the problems. We are facing a contrast. In the summer, we are thinking for a drop of water; in the rainy season, thousands of villages are washed away by the floods. This is a contrast because we have never applied our mind to this problem. Sir, if you do not take effective steps to tackle the inter-connected problems relating to the agriculture economy, if you neglect the basic industry of the country, your GDP will never rise. As mentioned by Mr. Premachandran, it has gone down by 25%. With all the technology, the modern technology, modern

industry, privatisation, globalisation, etc., if the agriculture continues to be neglected and not given the required thrust, this drought, सूखा एवं बाढ़ आते ही रहेंगे। With these words, Sir, I request the Government, though late, to pay proper attention to the agriculture which it deserves. Thank you very much.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : श्री रामचन्द्र खूंटिआ । इससे पहले आप शुरू करें, मैं एक बात आपको बता दूं कि कांग्रेस दल का केवल एक मिनट शेष है और अभी आप दो माननीय सदस्य बोलने वाले हैं । कृपया थोड़े-थोड़े समय में अपनी बात कह दें ।

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA (Orissa): Hon. Vice-Chairman, Sir, the year, 2002, has witnessed one of the worst drought situations affecting almost 14 States including Orissa. As you know, in 1999, there was super cyclone in Orissa; then there were floods; now, there is drought in 314 blocks of 30 districts. The situation is very serious. As you have suggested, I don't want to go into the details and make a political speech about the situation. I only want to give some suggestions. I think the Orissa Government has demanded an amount of Rs.815 crores and 12.91 lakh tonnes of foodgrains. But the quantity announced by the Central Government is not enough. I request that the demand of the Orissa Government should be considered once again and the Central Government should give adequate funds to meet the situation. We all know that, in Orissa, 30 districts, the KBK districts, the western districts and the coastal districts, are affected. I don't want to go into the details and make a political speech. But some Members had spoken about Madhya Pradesh and Rajasthan. The point is that when a person dies in Madhya Pradesh, it is said that he died due to starvation. But when it is said that 350 persons died in KBK districts and western districts of Orissa, the State Government and the Central Government are saying that it was not due to starvation; it was due to malnutrition and some diseases. That is not correct. I want to mention here that in Orissa there are 15,000 lift irrigation points, which could have been utilised to meet the drought situation. The State Government of Orissa has initiated a Pani Panchayat Scheme. They are forcing the agriculturists and the farmers to accept the Paani Panchayats. The State Government says that if they do not accept the Paani Panchayats, the lift irrigation points will not be made functional. Had the lift irrigation points been made functional, millions of hectares of land could have been utilised and the production target could have also been achieved. But that was not done. It is an artificial drought created by the State Government by not making the lift irrigation points, which are already existing, functional.

So far as the State Government is concerned, it is not taking any effective steps. There are always contradictions. Take the case of KBK districts. The Chief Minister said that the Central Government was pleased to sanction Rs.200 crores for the KBK districts. The Central Government also said that it had sanctioned the amount. But, till the beginning of November, only a sum of Rs.50 crores has been released and even that amount had not reached Orissa. Then, how do you expect us to utilise the amount of Rs.200 crores, which has been sanctioned for the KBK districts, the most backward districts of Orissa, before 31st March, 2003? Again, in the case of KBK districts, there is a long-term action plan, which has been submitted by the State Government of Orissa some five years ago. It has not been accepted by the Planning Commission till today, and the Central Government is also not taking any interest in it. We all know the history of KBK districts. We all know about the effects of super-cyclone in Orissa. In spite of all this, the Central Government has always adopted an apathetical attitude and not released the funds. The people are only hearing what the Ministers say. The Central Government says that it has released the funds. But the State Government says that the Central Government has not released the funds. There is a contradiction. This is the situation. I request the Central Government, through you, Sir, that this kind of attitude is detrimental to the interests of the general public, when the people of Orissa are affected by cyclone, floods and drought. They are in a distressful condition. The economy of Orissa is in a bad shape. In this situation, I demand that the Central Government should sanction a minimum amount of Rs.1,000 crores to meet the drought situation in Orissa, without any political consideration, without any quarrel between the State Government and the Central Government. Thank you.

SHRIMATI PREMA CARIAPPA (Karnataka): Sir, it is very unfortunate that our country is facing a severe drought this year. In Karnataka, more than 140 taluks have been officially declared as drought-hit areas. But there are many villages where people could not cultivate their land, due to a poor rainfall and, particularly, the people of Chikmangloor and Coorg districts, who are depending only on agriculture and perennial crops like coffee have been badly affected. Sir, due to poor rainfall, they could not cultivate their land and due to the decline in the price of coffee and also due to untimely rain, the coffee production has fallen. So, the people of this area have been affected very badly and whatever grants the Government has given to the State of Karnataka are very meagre, as compared to what has been given to the other States, particularly the BJP-ruled States in our

country. Our hon. Chief Minister made repeated requests for releasing foodgrains and relief. Till today we are waiting for that. Sir, I request the hon. Minister to release these foodgrains and also our State should not be given step-motherly treatment. Sir, it is high time that the Central Government thought of having a proper planning and a permanent solution to face these natural calamities like floods, cyclones and earthquakes. Sir, unless we have a proper planning, it would be very difficult to find a solution to this problem and we will have to face such a situation almost every year. Sir, I request the hon. Minister to see that they give to the Karnataka State more foodgrains and relief to our people.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : सूखे के महत्वपूर्ण विषय पर जो अल्पकालिक चर्चा थी, वह समाप्त हो गई है और इसका उत्तर माननीय कृषि मंत्री जी कल इस सदन में देंगे। अब हम कल शुक्रवार, 22 नवम्बर, 2002 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

The House then adjourned at forty seven minutes past five of the clock till eleven of the clock on Friday, the 22nd November, 2002.